



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 2019/माघ 9, 1940

No. 38]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 2019/MAGHA 9, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

अंतिम जाँच परिणाम

विषय - चीन जनवादी गणराज्य के मूल की / वहां से निर्यातित "पैरासिटामोल" के आयातों संबंधी पाटनरोधी जाँच की निर्णायक समीक्षा

फा. सं. 7/16/2018-डीजीएडी.—1. 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित 'पैरासिटामोल' (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।

2. यतः संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जाँच प्राधिकारी द्वारा 30 जनवरी, 2001 की अधिसूचना सं. 60/1/2000-डीजीएडी द्वारा शुरू की गई थी। प्राधिकारी द्वारा 16 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना सं. 60/1/2000-डीजीएडी द्वारा प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी किए गए थे और राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना सं. 89/2001-सीमाशुल्क दिनांक 6 सितम्बर, 2001 द्वारा अनंतिम शुल्क लगाया गया था। प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना सं. 60/1/2000-डीजीएडी दिनांक 22 जनवरी, 2002 के माध्यम से अंतिम जाँच परिणाम जारी किए गए जिसमें निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। अंतिम जाँच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना

सं. 29/2002-सीमाशुल्क दिनांक 27 मार्च, 2002 के द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधीशुल्क लगाया गया था। पहली निर्णायक समीक्षा सम्पन्न हुई और प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 15/20/2006-डीजीएडी दिनांक 23 जुलाई, 2007 द्वारा निर्णायक समीक्षा के अंतिम जाँच परिणाम जारी किए और केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं 99/2007-सीमाशुल्क दिनांक 3 सितम्बर, 2007 द्वारा नियत शुल्क लगाया गया था। दूसरी निर्णायक समीक्षा सम्पन्न हुई और प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 14/1009/2012-डीजीएडी दिनांक 26 अगस्त, 2013 द्वारा निर्णायक समीक्षा के अंतिम जाँच परिणाम जारी किए और केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं 26/2013-सीमाशुल्क दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 द्वारा नियत शुल्क लगाया गया था।

3. यतः नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1995 की धारा 9 क (5) के अनुसार यदि शुल्क की समाप्ति से पहले शुरू की गई समीक्षा में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं कि शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले न हटाया जाए तो उसे लागू करने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाता है।

4. और उक्त प्रावधान के होते हुए भी प्राधिकारी के लिए उपाय के समाप्त होने की तारीख से पहले तर्कसंगत समयावधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

5. यतः, समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे एडी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए यह याचिका मै. फार्मसन फार्मास्युटिकल गुजरात प्रा. लि. और मै. श्री कृष्णा फार्मास्युटिकल लि. (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) द्वारा दायर की गई है और मै. भारत कैमिकल्स, मै. ग्रेन्युल्स इंडिया लि. और मै. मेघमनी यूनिकैम एलएलपी द्वारा समर्थित है और इसमें चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित 'पैरासिटामोल' के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

6. घरेलू उद्योग की ओर से दायर पाटन और क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य सहित विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के मद्देनजर और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क(5) के अनुसार प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 24 मई, 2018 की अधिसूचना सं फा. सं. 7/16/2018-डीजीएडी जारी की जिसमें संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस बात की जाँच करने के लिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति होना जारी रहेगा या उसकी पुनरावृत्ति होगी, के लिए निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत की गई। संबद्ध देश से संबद्धवस्तु के आयातों पर पाटनरोधीशुल्क की वैधता को केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं. 39/2018-सीमाशुल्क दिनांक 20 अगस्त, 2018 के माध्यम से 24 मई, 2019 तक बढ़ा दिया गया है।

7. वर्तमान समीक्षा के दायरे में संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पूर्ववर्ती जाँचों के सभी पहलू शामिल हैं।

क. सामान्य प्रक्रिया

8. संबद्ध जाँच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है :

- i. प्राधिकारी के संबंधित नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जाँच की शुरुआत की कार्यवाही करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया।
- ii. प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 24 मई, 2018 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसमें चीन जन. गण. के मूल की और वहां से निर्यातित पैरासिटामोल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क जाँच की निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत की गई।

- iii. प्राधिकारी ने नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार भारत में चीन जन. गण. के दूतावास को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्रों के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों को जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियाँ भेजीं और उनसे जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की तारीख के 40 दिनों के भीतर लिखित में उनके विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।
- iv. प्राधिकारी ने संबंधित नियमावली के नियम 6(3) के अनुरूप आवेदन के अगोपनीय अंश की एक-एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में चीन जन. गण. के दूतावास को उपलब्ध कराई थी। आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति सार्वजनिक फाइल में भी रखी गई और अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षों को उपलब्ध कराई गई।
- v. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार चीन जन. गण. के उत्पादकों/निर्यातकों (जिनके व्योरे आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) से संगत सूचना मंगाने के लिए उन्हें निर्यातक प्रश्नावली भेजी और उन्हें लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया।

क) अनहुई बेई कैमिकल इंडस्ट्री कं लिमिटेड

ख) अनहुइ फुबोर फार्मास्युटिकल

ग) झेजियांग कंगले फार्मास्युटिकल कंपनी

घ) मैसर्स वानजाउ फार्मास्युटिकल फैक्ट्री

ङ) चांगशु हुआगांग फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड

च) हेबै जियांग ग्रुप कंपनी लिमिटेड

छ) जिआंगसु वर्ल्ड काइंडली फार्मास्युटिकल्स लि

ज) जिआंगसु गुओहेंग फार्मा केमिकल कंपनी लिमिटेड

झ) शंघाई बाइलियन केमिकल्स कंपनी लिमिटेड

ञ) लियोनयुआन सिटी बैयांग फार्मास्युटिकल

ट) रनकी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

ठ) अनिकुलु वन फार्मास्युटिकल्स कं. लि

vi. निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

क) मेसर्स अंकिउ लू एन फार्मास्युटिकल कं, लिमिटेड

ख) मेसर्स ए.एच.ए. इंटरनेशनल कं, लिमिटेड

ग) चीन सिनोपार्म इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन

घ) झेजियांग कैमिकल्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन

ङ) लियानयुनगांग कंगले फार्मास्युटिकल कं, लिमिटेड

च) झेजियांग कंगले फार्मास्युटिकल कं, लिमिटेड

छ) हेबै जिहेंग (ग्रुप) फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड

vii. चीन जन. गण. में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में चीन जन. गण. के दूतावास को पूरक प्रश्नावली भी इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे विहित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी को संगत सूचना प्रस्तुत कर दें।

viii. तथापि किसी भी निर्यातक ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।

- ix. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता एसोसिएशनों (जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए) को आयातक प्रश्नावली के साथ जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें प्राधिकारी को विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने की सलाह दी:-
- क) औरा फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लिमिटेड
 - ख) शालिना लेबोरेटरीज प्रा. लिमिटेड
 - ग) मेडिकामेन बायोटेक लि.
 - घ) एडकाँक इनग्राम लि.
 - ङ) सनोफी इंडिया लिमिटेड
 - च) फोरट्रेट्स (इंडिया) लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 - छ) इंडोको रेमेडीज लि।
 - ज) एस्ट्रा लाइफकेयर (इंडिया) प्रा. लिमिटेड
 - झ) जे.बी.केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.
 - ञ) यूनीलिक फार्मा प्रा. लिमिटेड
 - ट) मेडोफार्म
 - ठ) मिलान लेबोरेटरीज (इंडिया) प्रा. लिमिटेड
 - ड) एगोग फार्मा लिमिटेड
 - ढ) कॉम्बिटिक ग्लोबल कैपलेट प्राइवेट लिमिटेड
- x. तथापि संबद्ध वस्तु के किसी भी आयातक से प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
- xi. नियम 6(7) के अनुसार प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों को हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण के लिए सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया था।
- xii. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जाँच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें और उसे नियमावली के अनुसार प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक फाइल के रूप में रखा गया था।
- xiii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और क्षति रहित कीमत ज्ञात करने के लिए अनुबंध 111 में निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर संभव सीमा तक घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की जाँच की है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xiv. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की है। क्षति जाँच अवधि में अप्रैल 2014 मार्च - 2015 अप्रैल, 2015 मार्च - 2016 अप्रैल, 2016 मार्च - 2017 की अवधि तथा जाँच की अवधि शामिल है।
- xv. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षों से अतिरिक्त सूचना आवश्यक समझी गई सीमा तक मांगी गई थी। वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के सत्यापन आवश्यक रूप से अपेक्षित सीमा तक किया गया था।

- xvi.** वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) और डीजी सिस्टम्स से सौदा-वार आंकड़े मंगाए गए थे। प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों और सहयोगी निर्यातकों के आंकड़ों पर भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा और मूल्य के परिकलन के लिए भरोसा किया है।
- xvii.** नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने 29 अगस्त, 2018 को हुई मौखिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षों को मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। इस सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने वाले हितबद्ध पक्षों को मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। हितबद्ध पक्षों को विरोधी हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत विचारों के खंडन अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर दिया। प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों पर उचित ढंग से विचार किया है।
- xviii.** ऐसे निर्यातक, उत्पादक और अन्य हितबद्ध पक्ष जिन्होंने प्राधिकारी को न तो उत्तर दिया है और न ही इस जाँच से संगत सूचना प्रस्तुत की है को असहयोगी हितबद्ध पक्ष माना गया है।
- xix.** गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जाँच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें।
- xx.** इस दस्तावेज में *** गोपनीय आधार पर प्राधिकारी को प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का द्योतक है।
- xxi.** पीओआई के लिए विनियम दर इस प्राधिकारी द्वारा 1 अमरीकी डॉलर = 65.33 रुपया के रूप में लिया गया है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

9. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :

- i. वर्तमान जाँच के अधीन विचाराधीन उत्पाद का दायरे में 'पैरासिटामोल है जिसे एसिटेमिनोफेन के रूप में भी जाना जाता है' है जैसा पूर्ववर्ती जाँच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित है। पैरासिटामोल एक कार्बनिक रसायन है और इसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उपशीर्ष 2922.2933 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।
- ii. पैरासिटामोल एक सफेद पाउडर है। इसका रासायनिक सूत्र **C8H9NO2** है। पैरासिटामोल एक सामान्य एनाल्जेसिक और एंटीपीयरेटिक दवा है जिसका उपयोग बुखार, सिरदर्द और अन्य मामूली दर्द और पीड़ा से राहत के लिए किया जाता है। यह कई सर्दी और फ्लू की दवाओं और कई लिखी गई दर्द निवारक में एक प्रमुख घटक है।
- iii. चूंकि वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है और प्राधिकारी द्वारा पहले यथा अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू है इसलिए प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वर्तमान जाँच में पीयूसी का दायरा पूर्ववर्ती जाँचों के समान ही रहेगा।

ग.2 निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

10. किसी भी हितबद्ध पक्ष ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

11. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जाँच में विचाराधीन उत्पाद पैरासिटामोल है। पैरासिटामोल को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अधीन उपशीर्ष सं. 2922.2933 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

12. पूर्ववर्ती जाँचों में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार है : -

'मूल तथा पहली एसएसआर जाँच और वर्तमान निर्णायक समीक्षा जाँच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित 'पैरासिटामोल है जिसे एसिटेमिनोफेन के रूप में भी जाना जाता है' चूंकि वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाच है इसलिए इस जाँच में मूल जाँच तथा पहली एसएसआर जाँच में शामिल उत्पाद शामिल है'

13. चूंकि वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है और प्राधिकारी द्वारा पहले यथा अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू है इसलिए प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान जाँच में पीयूसी का दायरा पूर्ववर्ती जाँचों के समान ही रहेगा। इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्ष ने इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

14. अतः प्राधिकारी ने पीयूसी को निम्नानुसार माना है : -

'पूर्ववर्ती जाँच और वर्तमान निर्णायक समीक्षा जाँच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित 'पैरासिटामोल है जिसे एसिटेमिनोफेन के रूप में भी जाना जाता है' चूंकि वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है इसलिए इस जाँच में मूल जाँच में शामिल उत्पाद शामिल है'

*'पैरासिटामोल एक गंधहीन सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है। इसका रासायनिक सूत्र **C8H9NO2** है। पैरासिटामोल एक बल्क भेषज सक्रिय घटक है, जो एनाल्जेसिक और एंटीपीयरेटिक गुणों को प्रदर्शित करता है। इसका उपयोग आरएक्स और ओटीसी दवा के कई प्रकारों में पाउडर, दानों, इंजेक्टबल्स और गोलियों के रूप में किया जाता है। पैरासिटामोल एक कार्बनिक रसायन है और इसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमाशुल्क उपशीर्ष 2922.2933 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण, केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे में किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।'*

ग. समान वस्तु**ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

15. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यात की गई संबद्ध वस्तु और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों उत्पादों में मापदंडों जैसे कि भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन और टैरिफ वर्गीकरण आदि की दृष्टि से तुलनीय विशेषताएं हैं।

घ.2 निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध

16. किसी भी हितबद्ध पक्ष ने इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों पर प्रश्न नहीं उठाया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

17. प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी से नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देश से आयात की गई वस्तु के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशनों और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। आगे यह उल्लेख किया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पिछली जाँच में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के मुद्दे की जाँच की थी जिस पर आवश्यक संशोधनों के साथ वर्तमान समीक्षा में भी भरोसा किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित वस्तु,

पाटनरोधी नियमों के नियम 2 (घ) के अनुसार समान वस्तु हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

इ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

18. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं: -

- i. चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित पैरासिटामोल के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने के लिए याचिका मेसर्स फरम्सन फार्मास्यूटिकल्स गुजरात प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स श्री कृष्णा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर की गई है और मै. भारत केमिकल्स, मेसर्स ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड, और मेसर्स मेघमनी एलएलपी द्वारा समर्थित है।
- ii. मेसर्स श्री कृष्णा फार्मास्यूटिकल के अलावा अन्य याचिकाकर्ताओं ने विचाराधीन उत्पाद को आयात नहीं किया है। मेसर्स श्री कृष्णा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने केवल 30 मीट्रिक टन का आयात किया है, जो इसके उत्पादन, भारतीय उत्पादन और भारतीय मांग के संबंध में बहुत मामूली है।
- iii. याचिकाकर्ता भारतीय उत्पादन में एक प्रमुख हिस्सा रखते हैं और तदनुसार नियमों के अर्थ के भीतर "घरेलू उद्योग" का गठन करते हैं।
- iv. याचिकाकर्ता संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी भी निर्यातक या आयातक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 (3) के साथ पठित नियम 2 (ख) के अधीन एक पात्र घरेलू उद्योग है।

इ.2 निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध

19. हितबद्ध पक्षों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं: -

- i. पाटनरोधी शुल्क की लेवी पाटन मार्जिन पर निर्भर करती है और पाटनरोधी जाँच में घरेलू उद्योग को पर्याप्त सुरक्षा देने का कोई सिद्धांत नहीं है।
- ii. प्राधिकारी के समक्ष जाँच के अधीन उत्पाद से संबंधित सभी चार जाँचों में घरेलू उद्योग की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं हुए हैं जिन्हें निम्नानुसार देखा जा सकता है: -
 - क) मूल जाँच: यह देखा जा सकता है कि प्राधिकारी के समक्ष मूल जाँच में चार उत्पादक थे अर्थात् मेसर्स ट्राइटन लेबोरेटरीज लिमिटेड, मेसर्स वामसी लैब्स लिमिटेड, श्रीनिवास एग्रो इंडस्ट्रीज एंड ड्रग्स लिमिटेड और श्री कृष्णा फार्मास्यूटिकल्स लि. जिन्होंने जाँच में भाग लिया और क्षति संबंधी जानकारी दी।
 - ख) पहली निर्णायक समीक्षा: पहली निर्णायक समीक्षा में तीन उत्पादकों के नाम थे, श्री कृष्ण फार्मास्यूटिकल्स, मेसर्स फरम्सन एनाल्जेसिक्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स भारत केमिकल्स लि.।
 - ग) दूसरी निर्णायक समीक्षा: दूसरी एसएसआर में, श्री कृष्णा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और मेसर्स भारत केमिकल्स लिमिटेड ने क्षति संबंधी जानकारी दी।
 - घ) तीसरी निर्णायक समीक्षा - वर्तमान जाँच : वर्तमान जाँच में, पुनः केवल 2 उत्पादकों जैसे कि श्री कृष्णा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और मेसर्स फरम्सन एनाल्जेसिक्स प्रा. लिमिटेड ने भाग लिया है और क्षति संबंधी जानकारी प्रदान की है।
 - ङ) घरेलू उद्योग या घरेलू उत्पादकों का गठन सभी चार जाँचों में अलग-अलग हैं और यह मानना मुश्किल नहीं है कि घरेलू उत्पादकों का गठन उनकी इच्छा पर और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बदल दिया गया था,
 - च) यह देखा जा सकता है कि घरेलू उत्पादक जो पिछली जाँच अर्थात् मूल जाँच और दो निर्णायक समीक्षा जाँचों में याचिकाकर्ता थे, ने वर्तमान मामले में कोई जानकारी नहीं दी है।

- छ) याचिका में कोई विश्लेषण या कारण नहीं है कि वे उत्पादक, जो पहले की जाँच में याचिकाकर्ता थे, वर्तमान जाँच में जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं।
- ज) जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में भी, उन उत्पादकों के संबंध में कोई विश्लेषण नहीं किया गया है जो जानकारी नहीं दे रहे हैं।
- झ) मेसर्स ट्राइटन लेबोरेटरीज लिमिटेड का वर्ष 1998 में ग्रेनुल्स इंडिया लि. के साथ विलय कर दिया गया था। तथापि, मै. ट्राइटन लेबोरेटरीज लि. को इस तथ्य के बावजूद ग्रेनुल्स इंडिया लि. से एक अलग कंपनी के रूप में पेश किया गया था, कि 30 जनवरी 2001 को मूल जाँच की शुरुआत के समय इन दोनों का विलय हो गया था और मूल जाँच की शुरुआत के समय ट्राइटन लेबोरेटरीज के नाम वाली कोई कंपनी मौजूद नहीं थी। हालांकि, मूल जाँच के समय घरेलू उद्योग का हिस्सा बनने वाले घरेलू उत्पादकों ने प्राधिकारी को गुमराह किया और मूल जाँच में तथ्यों को गलत तरीके से पेश करके पाटनरोधी शुल्क लगवाया था।
- ञ) पहली निर्णायक समीक्षा में मेसर्स ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड को एक आयातक के रूप में दिखाया गया था और जाँच में शामिल नहीं किया गया था। मेसर्स ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड भारत में संबद्ध वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक है। पीओआई में इसकी बिक्री 579 करोड़ रुपये की रही है।
- ट) घरेलू उद्योग ने बावजूद इसके वह सबसे बड़ी कंपनी है, मेसर्स ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड को हुई क्षति की जानकारी नहीं दी है।
- ठ) पिछली दो निर्णायक समीक्षा जाँच में भी, उन जाँचों में सार्थक विश्लेषण और निष्कर्ष के लिए मेसर्स ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड से क्षति संबंधी कोई भी जानकारी नहीं ली गई थी। याचिका में या जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया है कि वर्तमान जाँच में इस उत्पादक ने जानकारी क्यों नहीं दी है जबकि ग्रेन्यूल्स इंडिया की समामेलित कंपनी अर्थात् ट्राइटन लेबोरेटरीज ने मूल जाँच में एक याचिकाकर्ता के रूप में भाग लिया और क्षति संबंधी जानकारी प्रदान की।
- iii. मेसर्स फरम्सन एनाल्जेसिक्स प्रा. लिमिटेड भी भारत में संबद्ध वस्तु के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। यह पहली निर्णायक समीक्षा में याचिकाकर्ता था और दूसरी निर्णायक समीक्षा में याचिकाकर्ता नहीं था। इस उत्पादक के संबंध में भी, याचिका में या जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में कोई कारण नहीं बताया गया है कि इस उत्पादक ने द्वितीय निर्णायक समीक्षा में जानकारी क्यों नहीं दी है और अब वर्तमान जाँच में क्षति संबंधी सूचना प्रदान कर रहा है।
- iv. उत्पादन में अधिकांश हिस्सा रखने वाले उत्पादक जो पिछली जाँच में याचिकाकर्ता थे, ने वर्तमान जाँच में क्षति संबंधी जानकारी प्रदान नहीं की है और कुल घरेलू उत्पादन में सीमित और कम हिस्सेदारी वाले उत्पादकों ने ही क्षति संबंधी जानकारी दी है, वर्तमान जाँच में शुल्कों को जारी रखे जाने का कोई आधार नहीं है क्योंकि प्रत्येक जाँच में घरेलू उद्योग की क्षति संबंधी काफी सूचना को जाँच से बाहर रखा गया है।
- v. वर्तमान मामला जाँच को समाप्त किए जाने और शुल्कों को हटाये जाने का उपयुक्त मामला है।

ड. 3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

20. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

21. यह याचिका मेसर्स फरम्सन फार्मास्युटिकल्स गुजरात प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स श्री कृष्णा फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर की गई है और मेसर्स भारत केमिकल्स, मेसर्स ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड और मेसर्स मेघमनी एलएलपी द्वारा समर्थित है। जाँच की शुरुआत के बाद, एक समर्थक कंपनी अर्थात् मेसर्स भारत केमिकल्स ने समस्त आवश्यक जानकारी प्रदान की है। तथापि प्राधिकारी ने उस पर विचार नहीं किया है क्योंकि इसे जाँच के अंतिम समय में प्रस्तुत किया गया था।
22. वर्तमान मामले में, निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत उत्पादकों के पास कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है और इस प्रकार पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में निर्धारित कानूनी अपेक्षा पूरी होती है। तथापि, निर्णायक समीक्षा के मामले में मूल जाँच में घरेलू उद्योग का गठन एक जैसा होना वांछनीय होता है।
23. प्राधिकारी ने नोट किया है कि रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के आधार पर आवेदकों का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। याचिकाकर्ताओं में मै. श्री कृष्णा फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने पीओआई के दौरान केवल *** मीट्रिक टन पीयूसी का आयात किया है, जो कि इसके उत्पादन के संबंध में ***% है और भारतीय मांग में ***% है, जो बहुत ही मामूली है और इसलिए प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच की शुरुआत करते हुए उन्हें एक पात्र घरेलू उद्योग माना है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने मौके पर एक दौरे के द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की पर्याप्तता और सटीकता से स्वयं को संतुष्ट किया था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता न तो भारत में किसी आयातक से और न ही संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक से संबंधित हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता कंपनियां पाटनरोधी नियमावली के संदर्भ में पात्र घरेलू उद्योग हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता कंपनियों का उत्पादन "कुल भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा" बनता है और इसलिए, नियमावली के नियम 2 (ख) और नियम 5 (3) के अधीन संबद्ध वस्तुओं के योग्यता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

ड. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

च. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

24. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- i. निर्यातकों/उत्पादकों ने गोपनीयता के प्रति अनावश्यक दावे किए हैं अथवा अपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई है जिसने दायर किए गए उत्तरों के संबंध में अर्थपूर्ण टिप्पणियां करने में घरेलू उद्योग को असमर्थ बनाया। उत्तरों को सही रूप से सूचीबद्ध अथवा संक्षेपीकरण नहीं किया गया है।
- ii. अगोपनीय पाठ में उपलब्ध कराई गई सूचना समझ से परे है। एन सी वी ने आंकड़ों की स्पष्ट व्याख्या उपलब्ध नहीं की है और इसी कारण से घरेलू उद्योग उस पर विस्तृत टिप्पणियां उपलब्ध कराने में असमर्थ है।
- iii. प्रश्नावली उत्तरों का अगोपनीय पाठ सकल रूप से अपर्याप्त और अपूर्ण हैं। संबंधित हितबद्ध पक्षकार ने ऐसी सारी सूचना को प्रकट नहीं किया है जिसे वे नियमों और इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाई जा रही पद्धति के अंतर्गत प्रकट करने के लिए बाधित हैं।

च.2 निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

25. निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- क. याचिकाकर्ताओं ने सीमाशुल्क और टैरिफ नियमावली, 1995 के नियम 7 के उल्लंघन में तर्कसंगत कारणों को उपलब्ध कराए बिना अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में निम्नलिखित सूचना को प्रकट नहीं किया है :-
- ख. डी जी सी आई एंड एस से सौदावार और छांटे गए आयात आंकड़े, कच्ची सामग्री /मूल आयात संबंधी आंकड़े और शामिल न किए गए सौदों की सूची को एक्सेल फाइल में सॉफ्ट प्रति में उपलब्ध नहीं कराया गया है।

- ग. पूर्ण पी ओ आई के आयात आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं और केवल 9 महीनों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।
- घ. निर्मित सामान्य मूल्य के मद-वार विवरणों को गोपनीय रखा गया है।
- ड. याचिकाकर्ताओं, समर्थक उत्पादकों और घरेलू उत्पादकों के कंपनीवार उत्पादन विवरणों को गोपनीय रखा गया है।
- च. पी ओ आई और पिछले तीन वर्षों के लिए कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। घरेलू उद्योग ने सिर्फ यह कहा है कि इसे याचिकाकर्ताओं की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तथापि, यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं की वेबसाइट पर कोई वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।
- छ. आवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि श्री कृष्णा फार्मास्युटीकल लिमि. ने संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा कारण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
- ज. घरेलू उद्योग ने समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभारों, अंतर्देशीय परिवहन, कमीशन और बैट समायोजन के लिए निर्यात कीमत से समायोजन का दावा किया है। तथापि, उनके द्वारा उक्त समायोजनों के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- झ. प्रतिशतांक शर्तों में लाभ/हानि और आर ओ सी ई को गोपनीय रखा गया है।
- ट. माननीय प्राधिकारी कृपया याचिकाकर्ताओं को उपर्युक्त सूचना को प्रकट करने और उसे उपलब्ध कराने का निर्देश दें ताकि निर्यातक/उत्पादक इस जाँच में प्रभावी टिप्पणियाँ करने में सक्षम हो सकें।

च. 3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

26. सूचना की गोपनीयता संबंधी बारे में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था की गई है:-

"7. गोपनीय सूचना :-

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जाँच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियाँ या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसके सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना की अवज्ञा कर सकते हैं।

27. गोपनीयता के संबंध में संबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए अनुरोधों की जाँच की गई है और तदनुसार उनका उल्लेख किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की उसे गोपनीय माने जाने की आवश्यकता के संबंध में जाँच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने सभी पक्षकारों के गोपनीयता संबंधी दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां भी संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया है।

च. विविध निवेदन**छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

28. उत्तर दायर करने वाले निर्यातक/उत्पादकों अर्थात् मै. एनक्यू लू अन फार्मास्युटीकल कं. लिमि., झेजियांग कांगले फार्मास्युटीकल कं. लिमि., मै. ए एच ए इंटरनेशनल कं. लि., झेजियांग कैमिकल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन एंड चाइना साइनोफार्म इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन द्वारा दायर निर्यातक प्रश्नावली स्वरूप में अपूर्ण है और इन में से किसी ने भी निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर (भाग-2) दायर नहीं किया है, जिसमें निर्यातकों से उनकी क्षमताओं, क्षमता विस्तार, सौदावार तीसरे देश को निर्यात, घरेलू बिक्रियों, मालसूची आदि से संबंधित सूचना की मांग की गई है। ये विवरण/सूचना निर्यातकों के संभावित व्यवहार की संकेतक है और इसलिए प्राधिकारी द्वारा उन्हें निर्णायक समीक्षा जाँच में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह अपूर्ण सूचना का मामला नहीं है बल्कि निर्धारित फॉर्मेट में अपेक्षित सूचना दायर करने में पूर्ण असमर्थता का है।
29. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन विश्वव्यापी रूप से काफी सीमित है। चूंकि विश्वव्यापी उत्पादन का लगभग 86 प्रतिशत भाग केवल भारत और चीन में होता है जिसमें से उत्पादन का 62 प्रतिशत भाग केवल चीन में होता है जबकि भारत का बाकी 26 प्रतिशत पर अधिकार है। अतः इस उद्योग में किसी प्रकार की रूग्णता भारतीय प्रयोक्ताओं को चीनी उत्पादकों की दया और एकाधिकार के अधीन रखती है।
30. यह कि शुल्क के अपर्याप्त रूप के विपरीत प्रभाव के कारण, देश में बड़े स्तर पर उत्पादन निलंबित था, जो प्रारंभ में पिछले दो दशकों में मौजूद था (ये सभी समापन 5 वर्षों से अधिक पुराने हैं और एडीडी के पिछले विस्तार से पहले के हैं)।
31. वाणिज्य पर 145वीं संसदीय स्थायी समिति जिसने भारतीय उद्योग पर चीनी वस्तुओं के प्रभाव का आकलन किया था, के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ए पी आई क्षेत्र को आयात से संरक्षण की जरूरत है और भारत सरकार भी भारत में एपीआई क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास कर रही है।
32. एक्टिव फार्मास्युटीकल इंग्रीडिएंट्स (ए पी आई) पर दिनांक 24 सितंबर, 2015 की कटोच समिति की रिपोर्ट में विशेष रूप से कहा गया है कि वाणिज्य मंत्रालय साथ ही अन्य विनियामक प्राधिकरणों को सम्मिलित कर ए पी आई क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक दीर्घावधिक कार्यनीति की आवश्यकता है जिसमें पाटनरोधी जैसे उपायों के विवेकपूर्ण और प्रचुर प्रयोग शामिल हैं।
33. "भारतीय फार्मा के लिए पद्धतियों और अवसरों" पर फरवरी, 2018 संस्करण की फिक्की रिपोर्ट में इस बात पर प्रमुख रूप से प्रकाश डाला गया है कि एपीआई आपूर्तियों के लिए चीन पर निर्भरता फार्मा उद्योग की कच्ची सामग्री की आपूर्ति के विघटनों और कीमत अस्थिरता को प्रकट करती है।
34. भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्युटीकल विभाग द्वारा जारी दिनांक 18 अप्रैल, 2018 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार देश में ए पी आई के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया गया है क्योंकि फार्मास्युटीकल क्षेत्र में अवसरों को लाने के लिए संगठित प्रयासों की आवश्यकता है।
35. बड़े पैमाने पर जनता को एक विनियामक तंत्र के जरिए भली भांति संरक्षित किया गया है क्योंकि पैरासिटामोल को औषधि नीति, 2015 में अनिवार्य औषधियों की राष्ट्रीय सूची के तहत शामिल किया गया है।
36. पैरासिटामोल देश में उपलब्ध सबसे सस्ती एपीआई में से एक है।

छ.2 निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

37. अन्य हितबद्ध पक्षकारों में से किसी ने भी कोई अनुरोध नहीं किया है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर (भाग-2), जो निर्यातकों से उनकी क्षमताओं, क्षमता विस्तार, तीसरे देश से सौदावार निर्यात, घरेलू बिक्रियों, मालसूची आदि पर सूचना की मांग करता है, को सहयोगी

निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा बाद में दायर किया गया था। उक्त उत्तरों के अगोपनीय पाठों को सार्वजनिक फाइल में रखा गया था ताकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों तथा उनकी पहुंच को सुगम बनया जा सके। प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा दायर साक्ष्य को एपीआई और अन्य बाजार सूचना जैसा कि फिक्की की रिपोर्ट, के संबंध में भारत सरकार की सोच के संबंध में नोट किया है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

39. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से ज्ञात निर्यातकों को उन्हें निर्धारित प्रपत्र और तरीके में सूचना उपलब्ध कराने की सलाह देते हुए प्रश्नावली भेजी। संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए :-

- i. मै. एंक्विलू अन फार्मास्युटीकल कं. लिमि.,
- ii. मै. ए.एच.ए. इंटरनेशनल कं. लिमि.,
- iii. चाइना साइनोफार्म इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन,
- iv. झेजियांग कैमिकल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन,
- v. लियान्गुंग कांगले फार्मास्युटीकल कं. लिमि.,
- vi. झेजियांग कांगले फार्मास्युटीकल कं. लिमि.,
- vii. हेबई जिहेंग (ग्रुप) फार्मास्युटीकल कं. लिमि.,

40. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क (1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

“व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

वशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम के देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु का निर्यात के देश से होकर केवल यांनांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम के देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

ज. घरेलू उद्योग के विचार

41. वर्तमान जाँच और प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

- i. चीन को इस कारण से गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माने जाने की जरूरत है कि चीन में लागत और कीमतें बाजार दबावों को उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं करते। अनुबंध-1 का पैरा 8 उन मापदंडों को निर्दिष्ट करते हैं जिन पर बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करते समय विचार किया जाना चाहिए। यह ये भी

समाविष्ट करते हैं कि जब तक इन शर्तों को पूरा/संतुष्ट नहीं किया जाता, चीनी लागतों और कीमतों को नहीं अपनाया जा सकता।

- ii. चीनी उत्पादकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वातावरण के अंतर्गत प्रचालन करने वाली कंपनियों के रूप में माने जाने की आवश्यकता है और प्राधिकारी अनुबंध-1 के पैरा-7 के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए आगे कार्रवाई कर सकते हैं।
- iii. आयात भारतीय बाजारों में पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं।
- iv. विभिन्न आयात सौदों की कीमतों में अंतर है जिसका तात्पर्य है कि चीनी उत्पादक समान उत्पाद की ऐसी कीमत पर बिक्री कर रहे हैं जो समान समय अवधि पर भी उल्लेखनीय रूप से भिन्न है और यह पीओआई की एक विशिष्ट परिघटना नहीं है बल्कि संपूर्ण क्षति अवधि में विस्तारित है।
- v. यह एक उपयुक्त मामला है जहां भारांशित औसत सामान्य मूल्य की भारांशित औसत निर्यात कीमत के साथ तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए, निर्दिष्ट प्राधिकारी से भारांशित औसत सामान्य मूल्य का परिकलन करने और इसकी पृथक निर्यात कीमत के साथ तुलना करने का अनुरोध किया जाता है और उन सभी आयात सौदों में, जहां पाटन मार्जिन ऋणात्मक है; इसे पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए शामिल किए जाने की जरूरत है।
- vi. समान समय पर रिपोर्ट किए जा रहे आयातों के संबंध में कीमतों में ऐसे उल्लेखनीय अंतर की कोई युक्तियुक्त कारण/औचित्य नहीं है।

ज.2 हितबद्ध पक्षकारों के विचार

42. उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

- i. वर्तमान जाँच में संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, जैसाकि घरेलू उद्योग द्वारा परिकलित किया गया है, कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और इसलिए, वर्तमान जाँच में याचिकाकर्ताओं द्वारा पाटन मार्जिन का निर्धारण त्रुटिपूर्ण है।
- ii. वर्तमान जाँच में चीन. जन. गण. में कंपनियों के लिए सामान्य मूल्य कृपया घरेलू बिक्रियों और संबद्ध वस्तुओं की लागत के आधार पर किया जाना चाहिए।
- iii. यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए है कि बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियों पर आधारित न होने के कारण चीनी उत्पादकों की घरेलू कीमतों या लागतों की उपेक्षा करने के लिए 15 वर्षों की अवधि, जैसाकि डब्ल्यू टी ओ के लिए चीन जनवादी गणराज्य के परिग्रहण प्रोटोकॉल के पैरा 15(क)(ii) में व्यवस्था की गई है, पैरा 15 (घ) की शर्तों में 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गई हैं और यह प्रचालनहीन हो गया है।
- iv. इस समय, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो माननीय प्राधिकारी को चीनी उत्पादकों को उनकी घरेलू कीमतों और लागतों की उपेक्षा करने के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था सिद्धांतों का प्रचालन करने के रूप में विचार करने में सक्षम बनाता है और चीन के लिए सामान्य मूल्य को उनकी घरेलू कीमतों और संबद्ध वस्तुओं की लागतों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- v. चीनी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु प्रयुक्त कोई अन्य पद्धति डब्ल्यू टी ओ के अंतर्गत भारत की बाध्यताओं के उल्लंघन में होगी।
- vi. उपर्युक्त अनुरोध के प्रति पूर्वाग्रह के बिना यह अनुरोध किया जाता है कि किसी अतिरिक्त कार्यविधि का अनुसरण किए बिना चीनी निर्यातकों के लिए उनके रिकॉर्डों के आधार पर सामान्य मूल्य का अनुमान किया गया है, घरेलू उद्योग ने यथोचित कार्य विधि, जैसी कि भारतीय

पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत निर्धारित की गई है, का अनुसरण किए बिना चीनी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का मनमाने ढंग से निर्धारित किया है।

- vii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित निर्मित सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन की लागत और 5 प्रतिशत पर लाभ की दर विचारित करने पर आधारित है। तथापि, निर्मित सामान्य मूल्य को मदवार विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
- viii. भारतीय लागतों और कीमतों पर आश्रित पद्धति का केवल तभी अनुसरण किया जाना चाहिए जब पैरा 7 के प्रारंभिक वाक्य में निर्धारित अन्य विकल्पों के आधार पर सामान्य मूल्य को निर्मित करना संभव नहीं हो।
- ix. पैरा 7 के प्रावधानों की शर्तों में, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सर्वप्रथम बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की पहचान किया जाना जरूरी है और केवल वहां, जहां ऐसे तीसरे देश से जरूरी आंकड़े प्राप्त करना संभव नहीं हो, एक उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए यदि अनिवार्य हो, सामान्य मूल्य को किसी अन्य उचित समायोजित आधार, जिसमें सामान्य उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में अदा की गई या अदायगी योग्य कीमत शामिल है, पर निर्धारित किया जा सकता है।
- x. घरेलू उद्योग संबंधित पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के बारे में किसी उचित विलंब के बिना सूचित करने के लिए बाध्य है, ताकि इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया जा सके।
- XI. कानून द्वारा निर्धारित अनिवार्य कार्य विधि का अनुसरण नहीं किया गया है क्योंकि हितबद्ध पक्षकारों को तीसरे देश के चयन के बारे में नोटिस नहीं दिया गया है। न ही हितबद्ध पक्षकारों से तीसरे देश के बारे में सुझाव देने और अनिवार्य सूचना उपलब्ध कराने के बारे में अनुरोध किया गया है।
- XII. अनिवार्य कार्य विधि का अनुसरण किए जाने के अभाव में, शेनयांग मात्सुशिता 2005 (181) ई एल टी 320 (एस सी) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए वर्तमान कार्यवाही को जारी नहीं नहीं रखा जा सकता।
- XIII. पैरा 7 की अनिवार्य कार्यविधि का अनुसरण करने में असफलता को सामान्य मूल्य के निर्धारण पर और परिणामस्वरूप पाटन मार्जिन पर पर्याप्त निहितार्थ हैं।
- XIV. इसलिए, वर्तमान जाँच में अनुबंध-1 के पैरा 7 में निर्धारित कार्यविधि का अनुसरण करने के लिए माननीय प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है।

ज. प्राधिकारी द्वारा जाँच

क. चीन में सामान्य मूल्य

- 43. जाँच शुरूआत किए जाने पर, प्राधिकारी ने चीन में उत्पादकों/निर्यातकों को जाँच शुरूआत नोटिस का उत्तर देने और सामान्य मूल्य के निर्धारण की संगत सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंड के अनुसरण में गैर बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा के खंडन के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को अनुपूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं। प्राधिकारी ने चीन सरकार से उनके देश में उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना उपलब्ध कराने की सलाह देने का अनुरोध किया। हालांकि, चीनी उत्पादकों में से किसी ने भी प्राधिकारी द्वारा जारी अनुपूरक प्रश्नावली का कोई उत्तर दायर नहीं किया।

44. तदनुसार, संबद्ध देश से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :

क. चीन जन.गण. में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

45. चूंकि, चीन जन. गण. के किसी भी उत्पादक ने अनुपूरक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियमों के अनुबद्ध-1 के पैरा 7 के अनुसरण में निर्धारित किया गया है। अन्य पद्धतियों के संबंध में रिकॉर्ड पर पर्याप्त सूचना की अनुपस्थिति में, जैसाकि पाटनरोधी नियमावली के अनुबद्ध-1 के पैरा-7 में प्रतिष्ठापित किया गया है, प्राधिकारी ने "किसी अन्य उचित आधार" पद्धति को अपना कर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
46. अतः प्राधिकारी ने भारत में समुचित रूप से समायोजित उत्पादन की लागत के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया है जिसमें विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्यय शामिल हैं। तदनुसार, चीनी निर्यातकों के लिए निर्मित सामान्य मूल्य *** रूपए प्रति किग्रा. निर्धारित किया गया है।

ख. चीन जन.गण. में निर्यात कीमत का निर्धारण

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. से नीचे उल्लिखित निर्यातकों ने प्राधिकारी को सूचना उपलब्ध कराई है जिसे निर्यात कीमत और पृथक पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए प्रयोग किया गया था।

- i. मै. एनक्यू अन फार्मास्युटीकल कं. लिमि.,
- ii. मै. ए.एच.ए. इंटरनेशनल कं. लिमि.,
- iii. चाइना साइनोफार्म इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन,
- iv. झेजियांग कैमिकल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन,
- v. लियांनयुनगांग कांगले फार्मास्युटीकल कं. लिमि.,
- vi. झेजियांग कांगले फार्मास्युटीकल कं. लिमि.,
- vii. हेबई जिहेंग (ग्रुप) फार्मास्युटीकल कं. लिमि.,

दायर किए गए उत्तरों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दिए गए उत्तरों का निम्नानुसार विश्लेषण किया है :-

मै. एनक्यू लू अन फार्मास्युटीकल कं. लि. (उत्पादक) और मै. ए एच ए इंटरनेशनल कं. लि., चाइना साइनोफार्म इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड झेजियांग कैमिकल्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. एनक्यू लू अन फार्मास्युटीकल कं. लि. ने भारत को सीधे ही संबद्ध वस्तुओं का *** मी.टन निर्यात किया है और *** मी.टन अपने ट्रेडर्स मै. ए एच ए इंटरनेशनल कंपनी लिमि., चाइना साइनोफार्म इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और झेजियांग कैमिकल्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के माध्यम से निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि एनक्यू लू अन फार्मास्युटीकल कंपनी ने *** अम.डॉ./मी.ट. की निर्यात कीमत रिपोर्ट की है और वहीं ए एच ए इंटरनेशनल कं. लिमि., चाइना साइनोफार्म इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और झेजियांग कैमिकल्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ने क्रमशः *** अम.डॉ., *** अम.डॉ./मी.ट. और *** अम.डॉ./मी.ट. की निवल निर्यात कीमत रिपोर्ट की है।
49. उत्पादकों/निर्यातकों ने अंतर्देशीय माल भाड़ा, समुद्री माल भाड़ा और समुद्री बीमा, क्रेडिट लागत, पत्तन व्ययों और वैट के कारण कीमत समायोजन का दावा किया है। प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक के लिए कारखानागत निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। उक्त उत्पादक और इसके संबंधित ट्रेडर्स की भारित

औसत निर्यात कीमत को तत्पश्चात उक्त निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों की कुल मात्रा पर विचार करते हुए इसे *** अम.डॉ./मी.ट. पर निर्धारित किया गया है।

मै. लियानयुनगांग कांगले फार्मास्युटीकल कं. लि. (उत्पादक) और मै. झेजियांग कांगले फार्मास्युटीकल कं. लि.

50. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. लियानयुनगांग कांगले फार्मास्युटीकल कं. ने अपने ट्रेडस मै. अर्थात् झेजियांग कांगले फार्मास्युटीकल कं. लिमि. के माध्यम से *** मी.ट. निर्यात किया है। उन्होंने अंतर्देशीय मालभाड़ा, समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, क्रेडिट लागत, पत्तन व्ययों और वैट के कारण कीमत समायोजन का दावा किया है। उत्पादक/ट्रेडर द्वारा दावा किए गए समायोजन के पश्चात, प्राधिकारी ने *** अम.डॉ./मी.ट. के रूप में कारखानागत निर्यात कीमत को निर्धारित किया है।

मै. हेबेई जिहेंग (ग्रुप) फार्मास्युटीकल कं. लि. (उत्पादक)

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. हेबेई जिहेंग (ग्रुप) फार्मास्युटीकल कं. लि. ने भारत को सीधे ही *** मी.ट. निर्यात किया है। निर्यातक ने अंतर्देशीय मालभाड़ा, समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, क्रेडिट लागत, पत्तन व्ययों और वैट के कारण कीमत समायोजन का दावा किया है। तदनुसार, उत्पादक/व्यापारी द्वारा दावा किए गए व्ययों के समायोजन के पश्चात, प्राधिकारी ने *** अम.डॉ./मी.ट. के रूप में कारखानागत निर्यात कीमत निर्धारित की है।

ग. **पाटन मार्जिन का निर्धारण**

52. **संबद्ध देश से सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए पी ओ आई के दौरान पाटन मार्जिन नीचे सारणी में उपलब्ध कराए गए अनुसार निर्धारित किया गया है :-**

कंपनी का नाम (उत्पादक) (पीओआई)	कंपनी का नाम (निर्यातक)	सीएनवी अम.डॉ./ मी.ट.	एनईपी अम.डॉ./ मी.ट.	पाटन मार्जिन अम.डॉ./मी. ट.	डीएम %	रेंज
मै. एन्क्यू लू एन फार्मास्युटीकल कं. लि.	मै. ए.एच.ए. इंटरनेशनल कं. लि.	***	***	***	***	0-10
	चाइना सिनोफार्म इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन					
	झेजियांग कैमिकल्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन					
लियानयुनगांग कांगले फार्मास्युटीकल कं. लि.	झेजियांग कांगले फार्मास्युटीकल कं. लि.	***	***	***	***	0-(10)
हेबेई जिहेंग (ग्रुप) फार्मास्युटीकल कं. लि.		***	***	***	***	10-20

घ. संपूर्ण चीन जन.गण. के पाटन मार्जिन का निर्धारण

- (क) समग्र रूप में देश के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना करते हुए, संबद्ध देश के लिए पाटन मार्जिन को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

विवरण अम.डॉ./किग्रा.-रू./किग्रा. (पीओआई)	अम.डॉ./किग्रा.	रू./किग्रा.
सामान्य मूल्य	***	***
निवल निर्यात कीमत	***	***
पाटन मार्जिन	***	***
पाटन मार्जिन %	***	***
रेंज %	10-20	10-20

- (ख) डी जी सी आई एंड एस के सौदावार आंकड़ों का विस्तार से विश्लेषण करने के पश्चात यह अवलोकन किया गया है कि चीन जन.गण. के कुल आयातों से अर्थात् *** मी.ट. में से ***% आयात पाटित हैं और ***% क्षतिपूर्ण हैं।

ज. क्षति निर्धारण और क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जाँच

53. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- निर्णायक पुनरीक्षा का स्वरूप मूल जाँच से भिन्न है क्योंकि यदि पाटनरोधी शुल्क को हटा दिया जाता है तो पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना पर अधिक ध्यान केन्द्रित होता है। पुनरीक्षा मामलों के लिए वर्तमान क्षति अथवा वर्तमान पाटन की उपस्थिति की जाँच करना जरूरी नहीं समझा गया है जहां क्षति की संभावना अधिक महत्वपूर्ण है।
- क्षति निर्धारण के संबंध में, यदि पाटनरोधी शुल्क का वांछित प्रभाव हुआ होता तो पाटनरोधी शुल्क प्रवृत्त होने की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार होने की संभावना थी।
- यह आकलन कि क्या क्षति जारी रहेगी अथवा उसकी पुनरावृत्ति होगी, भावी घटनाओं की एक प्रति तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करेगा, जो पाटित आयातों, कीमतों और घरेलू उद्योग पर के प्रक्षेपित स्तर पर आधारित होगा।
- निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस प्रश्न पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण रूप से हानि होने की संभावना है, यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है।
- इस समय ऋणात्मक कीमत कटौती विद्यमान है। यह प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क के कारण है। पाटनरोधी शुल्क को निरस्त किए जाने पर स्थिति के विपरीत होने की संभावना है।
- पाटनरोधी शुल्क के प्रवृत्त होने के कारण विक्रय कीमत और आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि हुई है। पाटनरोधी शुल्क को निरस्त करने की स्थिति में, आयातों से कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण प्रभाव होने की पूरी संभावना है।
- घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और विक्रयों में वृद्धि हुई है। हालांकि, इस स्तर पर वर्तमान शुल्कों को समाप्त करने से क्षमता उपयोग में महत्वपूर्ण रूप से गिरावट आएगी।

- viii. आधार वर्ष के बाद से घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर लाभ, नकद लाभ तथा आय में वृद्धि हुई है।
- ix. पूरी जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा स्थिर बना रहा है। पाटनरोधी शुल्क को निरस्त किए जाने की स्थिति में, संबद्ध देश से पाटित आयात का उल्लेखनीय मात्रा में प्रवेश दुबारा आरंभ हो जाएगा जो घरेलू बाजार का बाजार हिस्सा अभिग्रहित कर लेंगे।
- x. अधिकतर मापदंडों की शर्तों में घरेलू उद्योग की वृद्धि ने सुधार दर्शाया है। यह प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क के कारण है। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में स्थिति के विपरीत होने की संभावना है।
- XI. वर्तमान मामले में, संबद्ध देश से निर्यात कीमत समय अवधि की शर्तों में उल्लेखनीय रूप से भिन्न है और इसलिए यह एक उचित मामला है जहां भारित औसत सामान्य मूल्य की भारित औसत निर्यात कीमत के साथ तुलना नहीं की जा सकती।
- XII. निर्दिष्ट अधिकारी से भारित औसत सामान्य मूल्य पर विचार करने और इसकी पृथक निर्यात कीमत के साथ तुलना करने का अनुरोध किया जाता है और उन सभी आयात सौदों में जहां पाटन मार्जिन ऋणात्मक है, वहां इसे पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए शामिल न किए जाने की आवश्यकता है।
- XIII. अवधि, जिसके लिए शुल्क प्रवृत्त है, यह निर्धारण करने के लिए असंगत है कि क्या शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता है। कानून में शुल्कों के विस्तार की व्यवस्था की गई है यदि ऐसे शुल्कों को निरस्त करने के कारण पाटन या क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना हो सकती है। अन्य देशों जैसे कनाडा, यूएसए, ब्राजील और यूरोपीय संघ के अभ्यास के अनुसार, शुल्कों के 15 से अधिक वर्षों के लिए लागू किया जा सकता है, चाहे संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात न हो रहा हो।

झ.2 निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

54. निर्यातकों द्वारा निम्नानुसार अनुरोध किए गए हैं :-

- i. वर्तमान जाँच में घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है और क्षति जाँच अवधि में घरेलू उद्योग के सभी क्षति मापदंडों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
- ii. संबद्ध वस्तुओं के आयात के प्रति पाटनरोधी शुल्क 17 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है और वर्तमान मामला कोई विशेष मामला नहीं है जहां शुल्कों को और 5 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की आवश्यकता है।
- iii. संबद्ध देश से भारत को आयातों की बहुलता शुल्कमुक्त योजना के अंतर्गत है जैसे भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही अग्रिम लाइसेंस, डी ई पी बी आदि, जो शुल्क के अधीन नहीं हैं।
- iv. चाहे ऐसे आयातों को क्षति के विश्लेषण और क्षति की संभावना के लिए शामिल किया गया है और पाटनरोधी शुल्क की अनुशंसा की गई है, तथापि उक्त शुल्क मुक्त स्कीमों के अंतर्गत किए गए आयात किसी पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन नहीं होंगे और भारत में प्रवेश करते रहेंगे।
- v. माननीय प्राधिकारी के समक्ष सभी चार जांचों में घरेलू उद्योग के गठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। इसलिए, यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इस समय घरेलू उद्योग प्रभावित हो रहा है।

- vi. भारत में जाँच अवधि में 579 करोड़ रूपए की बिक्री करने वाले संबद्ध वस्तु के सबसे बड़े उत्पादक अर्थात् ग्रेन्यूल्स इंडिया को सभी 3 निर्णायक समीक्षा से अलग रखा गया है और कोई क्षति संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। सभी 3 निर्णायक समीक्षा जाँचों में सीमित सूचना के आधार पर क्षति और क्षति की संभावनाओं का विश्लेषण घरेलू उद्योग की स्थिति की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर सकता और इसलिए वर्तमान मामले में, शुल्क को और 5 वर्ष की अवधि के लिए विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है।
- vii. चीन जन.गण. (मामला सं. 15/2/2011-डी जी ए डी और अंतिम जाँच परिणाम दिनांक 20 मई, 2013) से ड्राई सैल बैटरीज से संबंधित अंतिम जाँच परिणाम को जारी करते समय प्राधिकारी ने धारित किया है कि 10 वर्षों के बाद भी पाटनरोधी शुल्कों को केवल विशेष मामलों में लागू किया जाना चाहिए।
- viii. यदि, पाटनरोधी शुल्क का विस्तार न किए जाने के पश्चात संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि होती है तो घरेलू उद्योग कभी भी नए पाटनरोधी जाँच को आरंभ करने के लिए आवेदन दायर कर सकता है।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

- 55. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 (क) (5) के अनुसार लागू किया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि वह पहले रद्द न किया गया हो, ऐसे प्रत्यारोपण की तारीख से पांच वर्षों के समाप्त होने पर प्रभाव करना बंद कर देगा बशर्ते कि यदि किसी पुनरीक्षा में, केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसे शुल्क को समाप्त करने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना हो सकती है, तो वह समय-समय पर, ऐसे प्रत्यारोपण की अवधि को और पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ सकती है और ऐसी विस्तारित अवधि ऐसे विस्तार के आदेश की तारीख से आरंभ होगी।
- 56. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जाँच के लिए, प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-II (iv) के अनुसरण में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांकों पर विचार किया है जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, विक्रय मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि।
- 57. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जाँच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जाँच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"
- 58. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.1 और नियमावली के अनुबंध-II में इन दोनों की तथ्यपरक जाँच की व्यवस्था है, (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव। पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जाँच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जाँच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती।

59. इस संबंध में प्राप्त अनुरोधों पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जाँच को आगे बढ़ाने से पहले घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति यदि कोई हो, की जाँच को आगे बढ़ाया है।

(i) मांग/प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण

60. प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग या प्रत्यक्ष खपत को परिभाषित किया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग नीचे दी गई है :—

*अप्रैल 17 से मार्च 18

मांग	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	104	108	108
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	114	108	110
से आयात					
चीन	मी.ट.	4,356	1,930	2205	2969
अन्य देश	मी.ट.	79	115	30	65
कुल मांग	मी.ट.	48,251	50,295	49,603	50,770

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में मांग ने वृद्धि दर्शायी है, हालांकि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 2016-17 में मामूली गिरावट आई है। मांग में पूर्ववर्ती वर्ष और आधार वर्ष दोनों की तुलना में जाँच की अवधि में एक बार फिर वृद्धि हुई।

(ii) पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव और घरेलू उद्योग पर उसका प्रभाव : आयात और बाजार हिस्सा

62. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार करना अनिवार्य है कि क्या या तो कुल रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष पाटित आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। नीचे दी गई सारणी आयात मात्रा और बाजार हिस्से के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है:-

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई
चीन	मी.ट.	4,356	1,930	2205	2,969
अन्य देश	मी.ट.	79	115	30	65
कुल आयात	मी.ट.	4,434	2,045	2235	3034
मांग में बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	%	***	***	***	***
संबद्ध देशों से आयात	%	9%	3.8%	4.44%	5.84%
अन्य देशों से आयात	%	0.16%	0.22%	0.06%	0.11%
कुल मांग	%	100	100	100	100

63. यह देखा गया है कि आयात मात्रा में 2015-16 तक गिरावट आई और तत्पश्चात उसमें वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की मांग में बाजार हिस्सा कमोबेश स्थिर बना रहा है।

(iii) घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

क. कीमत कटौती

64. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना जरूरी है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत के साथ तुलना करने पर पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है अथवा ऐसे आयातों के प्रभाव ने अन्यथा रूप से कीमतों में महत्वपूर्ण सीमा तक ह्रास किया है अथवा कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित किया है, जो अन्यथा उल्लेखनीय रूप से घटित हुआ होता। इस संबंध में, उत्पाद के पहुंच मूल्य और व्यापार के समान स्तर पर सभी छूटों और करों को घटाकर घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के बीच एक तुलना की गई है। प्राधिकारी ने आयातों की पहुंच कीमत की संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ तुलना की है।

कीमत कटौती

विवरण	इकाई	पीओआई
चीन जन.गण. से आयातों की पहुंच कीमत	Rs./Kg	250.06
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./किग्रा.	***
कीमत कटौती	रु./किग्रा.	(***)
कीमत कटौती	%	(***)
रेंज		(0-10)

उपर्युक्त से, प्राधिकारी ने नोट किया है कि कोई कीमत कटौती नहीं हुई है।

65. घरेलू उद्योग के अनुरोधों और विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों में इस बात में कोई विवाद नहीं है कि संपूर्ण आयात अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए थे और इसलिए इन आयातों पर न तो सीमाशुल्क न ही एडीडी अदा किए गए थे।

ख. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

66. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास या न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव महत्वपूर्ण सीमा तक कीमतों में ह्रास करता है अथवा कीमत में वृद्धि को नियंत्रित करता है जो अन्यथा महत्वपूर्ण सीमा तक घटित हुआ होता, प्राधिकारी ने क्षति अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों पर विचार किया है। स्थिति नीचे दी गई सारणी के अनुसार दर्शायी गई है।

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई
बिक्री की लागत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	89	87	99
बिक्री कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	93	89	103
आयातों की पहुंच कीमत	रु./किग्रा.	265	266	238	250
प्रवृत्ति		100	102	87	94

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि पी ओ आई में आधार वर्ष की तुलना में बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है, पीओआई में बिक्रियों की लागत में मामूली गिरावट आई है। आधार वर्ष की तुलना में, पीओआई में संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य में गिरावट आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने पूर्ण क्षति अवधि के दौरान बिक्रियों की लागत में वृद्धि के समानुपात में अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि की है। इसलिए, कोई कीमत ह्रास या न्यूनीकरण नहीं हुआ है।

(iv) घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

68. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव, एवं (ख) ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जाँच का प्रावधान है। जहां तक पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जाँच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जहां तक कि पाटित के कीमत प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जाँच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे उत्पादों के प्रभाव से कीमत में काफी अधिक मात्रा में अन्यथा गिरावट आई है अथवा होने वाली इस वृद्धि में रुकावट आई है जो अन्यथा काफी अधिक स्तर तक बढ़ गई होती।
69. तदनुसार, घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मापदंडों का यहां नीचे विश्लेषण किया गया है :-

(क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

70. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा का विवरण निम्नानुसार है :-

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई
क्षमता	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	प्रवृत्ति	100	100	100	100
उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	प्रवृत्ति	100	103	111	126
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	प्रवृत्ति	100	103	111	126
पीयूसी के लिए घरेलू बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	प्रवृत्ति	100	113	116	117

उपर्युक्त जानकारी से, प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं :-

- (क) अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर बनी रही है।
- (ख) घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्रियां और क्षमता उपयोग क्षति अवधि में स्थिर बने रहे हैं।

(ख) मांग

मांग	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	104	108	108

अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	114	108	110
से आयात					
चीन	मी.ट.	4,356	1,930	2205	2969
अन्य	मी.ट.	79	115	30	65
कुल मांग	मी.ट.	48,251	50,295	49,603	50,770

71. उपरोक्त जानकारी से यह ध्यान दिया जाता है कि: -

i) घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री आधार वर्ष से बढ़ी है।

ii) इसी अवधि के दौरान कुल मांग में वृद्धि के बावजूद चीन और अन्य देशों के आयात में आधार वर्ष से गिरावट आई है।

(ग) **मांग में बाजार हिस्सा**

72. मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से के विवरण नीचे सारणी में दिए गए हैं :-

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	%	***	***	***	***
संबद्ध देश से आयात	%	9%	3.8%	4.44%	5.84%
अन्य देश से आयात	%	0.16%	0.22%	0.06%	0.11%
कुल मांग	%	100	100	100	100

73. ये देखा गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति अवधि में मामूली वृद्धि हुई है।

क. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

74. लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार है :-

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई
लाभ/(हानि)	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	375	225	325
नकद लाभ	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	240	165	255
पूंजीगत निवेश पर आय - एनएफए	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	173	90	136

75. उपर्युक्त सारणी से यह देखा गया है कि आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई में लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेशों पर आय में वृद्धि हुई है।

क. मालसूची

76. घरेलू उद्योग के पास माल सूचियां निम्नानुसार हैं :-

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई
औसत	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	125	130

77. यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं का औसत मालसूची स्तर एक वृद्धिकारक प्रवृत्ति दर्शाता है।

ख. रोजगार, लाभप्रदता और वेतन

78. रोजगार उत्पादकता और वेतन के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार है :-

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई
कर्मचारियों की सं.	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	118	119
मजदूरी	लाख रूपाए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	138	168
उत्पादकता/व्यक्ति/दिवस	किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	94	106

79. उपर्युक्त से यह देखा गया है कि आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई के दौरान कर्मचारियों की संख्या, वेतन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

क्षति का परिमाण और क्षति मार्जिन

80. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III की शर्तों में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई है, पीओआई के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देश से निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है और इस प्रकार तैयार किया गया क्षति मार्जिन निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	चीन (पीओआई)
1	आयात मात्रा	मी.ट.	2969
2	क्षति रहित कीमत	रू./किग्रा.	***
3	पहुंच कीमत	रू./किग्रा.	***
4	क्षति मार्जिन	रू./किग्रा.	(***)
5	क्षति मार्जिन	%	(***)
	क्षति मार्जिन रेंज		0-(10)

झ. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना

81. चूंकि, यह एक निर्णायक समीक्षा जाँच है और प्राधिकारी यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की अनुमति दी जाए तो सतत पाटन एवं परिणामस्वरूप क्षति के संभावित परिदृश्य की अब जाँच करते हैं।

ञ.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

82. पाटन जारी रहने और परिणामस्वरूप बार-बार क्षति होने की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.1 और सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा की 9क(5) के अवलोकन से यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि निर्णायक समीक्षा जाँच के विधायन के पीछे मुख्य आशय निम्नलिखित की जाँच करना है:
 - क. क्या पाटन जारी है और यदि हाँ तो क्या यह जारी रहने की संभावना है;
 - ख. जिन मामलों में पाटन जारी नहीं रहा, क्या पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में पाटन बार-बार होगा;
 - ग. क्या घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हुई और यदि हाँ तो क्या घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने की संभावना है;
 - घ. जिन मामलों में घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हुई है, क्या घरेलू उद्योग को क्षति पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में बार-बार होने की संभावना है;
- ii. मूल जाँच और परिणामस्वरूप निर्णायक समीक्षा जाँचों में भी काफी पाटन की मौजूदगी सिद्ध हुई। पूर्व तथा प्रथम निर्णायक समीक्षा जाँच में पाटन मार्जिन काफी अधिक था।
- iii. घरेलू बाजार तथा दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया जैसे अन्य देशों में चीन से संबद्ध सामानों के पाटन का एक लंबा इतिहास है।
- iv. सतत पाटन केवल अंतिम निर्णायक समीक्षा जाँच के अंतिम निष्कर्ष के बाद ही कम हुआ था। उससे पूर्व घरेलू उद्योग को काफी पाटित आयातों के कारण निरंतर क्षति हो रही थी, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा समीक्षा मामलों में अधिसूचित पूर्व अंतिम जाँच परिणामों में उल्लेख किया गया।
- v. इन आयातों का काफी स्तर 2015-16 से गिरना आरंभ हुआ। तथापि, यह नोट करना व्यावहारिक है कि घरेलू उद्योग पाटन के विगत क्षतिकारक प्रभावों से अब भी उसी स्तर पर है और इस प्रकार सुभेद्य स्थिति में है। पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने से घरेलू उद्योग को गहन क्षति होने की संभावना है।
- vi. यह दिखाई देगा कि घरेलू उद्योग में पिछले पांच वर्षों से पाटनरोधी शुल्क के संरक्षण का लाभ लिया है, तथ्य यह है कि घरेलू उद्योग पिछले पांच वर्षों से ही प्रभावी रूप से संरक्षित रहा है। चीनी उत्पादकों ने पाटन जारी रखा और उससे पाटनरोधी शुल्क लागू रहने के बावजूद एक दशक तक घरेलू उद्योग को क्षति हुई।
- vii. निर्धारित मात्रा में निर्धारण से शुल्क के स्वरूप में परिवर्तन से आयातों में कमी आई है। पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने से आयातों में वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि उत्पादकों के पास पर्याप्त अधिशेष क्षमताएं उपलब्ध हैं। आयातों में गिरावट पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के कारण है।
- viii. सतत पाटन के कारण विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने वाले कई संयंत्र देश में बंद हो गए हैं जो निम्नलिखित हैं:
 - मैसर्स ट्रीटोन लैबोरेट्रीज लि.
 - मैसर्स वामसी लैब्स लि.
 - मैसर्स श्रीनिवासा एग्रो इंडस्ट्रीज एंड ड्रग्स लि .
 - मैसर्स पैन ड्रग
 - मैसर्स एल्फा ड्रग
 - मैसर्स ग्लैक्सोमिथक्लाइन फार्मास्युटिकल्स लि .
 - मैसर्स थेक्सा फार्मा प्रा.लि .
 - मैसर्स वानी फार्मा लैब्स लि.
 - रोहिणी केमिकल
 - फॉर्च्यून केमिकल
 - दिनेश फार्मास्युटिकल

- डॉजैन्स कंपनी .
 - साबू मेडिकेम
- ix. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन वैश्विक रूप से काफी सीमित है। लगभग 86 प्रतिशत वैश्विक उत्पादन भारत और चीन में है। 62 प्रतिशत उत्पादन केवल चीन में है जबकि भारत का हिस्सा 24 प्रतिशत का है। इस प्रकार, इस उद्योग में किसी रुग्णता से वैश्विक मांग चीनी उत्पादकों की दया पर रह जाएगी।
- x. निर्यातकों द्वारा दायर किए गए प्रश्नावली के उत्तर सिद्ध करते हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों में संबद्ध सामानों का आयात है।
- xi. वर्तमान परिदृश्य में घरेलू उद्योग पाटन के प्रतिकूल प्रभावों से अब भी जूझ रहा है और उसने अपने आर्थिक मानदंडों के संदर्भ में आंशिक वृद्धि दर्शाई है। यदि पाटनरोधी शुल्क प्राधिकारी द्वारा समाप्त किए जाते हैं तो वह वृद्धि विपरीत हो जाएगी।
- xii. घरेलू उद्योग को उसके निष्पादन में और ह्रास नहीं हुआ है, इसका एक मात्र कारण यह है कि आयातों की मात्रा लागू शुल्कों के कारण कम थी। तथापि, संबद्ध देश में उत्पादकों के पास काफी खाली क्षमताएं हैं जो भारत में पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में निर्यातों की इन अनुपयुक्त क्षमताओं का उपयोग करने और भारतीय बाजार में लाने की संभावना है।
- xiii. विदेशी उत्पादक निर्यातोन्मुख हैं क्योंकि उनकी क्षमताएं संबद्ध देश में घरेलू मांग से कहीं अधिक हैं। संबद्ध देश में संबद्ध सामानों का उत्पादन 2.21 लाख मी. टन क्षमताओं के विरुद्ध 1 लाख मी. टन की रेंज में हैं जबकि चीन में उत्पाद के लिए घरेलू मांग काफी कम लगभग 20,000 मी. टन है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि निर्यातकों ने 1 लाख मी. टन उत्पादन में से संबद्ध देश में मांग से कहीं अधिक क्षमताएं बनाई हैं जो लगभग 80 प्रतिशत निर्यातों के लिए हैं।
- xiv. निर्यातक भारत में ही पाटन नहीं कर रहे हैं बल्कि अन्य देशों में भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, जिन कीमतों पर इन देशों को सामानों की आपूर्ति की गई है, वह क्षति रहित कीमत से कम है। अतः यह निष्कर्ष निकालना उपयुक्त है कि निर्यातकों के भारत में भी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में पाटित और क्षति रहित कीमतों पर बिक्री करने की संभावना है।
- xv. वैश्विक रूप से विभिन्न देशों में संबद्ध देश से निर्यात कीमत संबद्ध देश से विभिन्न देशों को वैश्विक रूप से निर्यात के काफी अनुपात के संबंध में भारत में निर्यात कीमत से काफी कम है। इन तीसरे देशों के निर्यातों में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन भारत में निर्यात के संबंध में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से अधिक हैं।
- xvi. चूंकि, भारत तीसरे देशों की तुलना में अधिक कीमत आकर्षक बाजार है, अतः निर्यातक शुल्क हटाए जाने की स्थिति में अन्य देशों से भारत को अपने सामान भेजना बेहतर मानेंगे ताकि वे अपना लाभ बढ़ा सकें और बाजार दे सकें। इस पर विचार करते हुए कि निर्यातकों की इन तीसरे देश के बाजारों में कोई प्रतिबद्धता नहीं है और उनके लिए पूरा मानदंड उनके उत्पाद की कीमत है, उनके द्वारा प्राप्त कीमत है।
- xvii. शुल्क लगाए जाने के बाद आयातों में गिरावट और इन आयातों में सकारात्मक पाटन मार्जिन का अर्थ शुल्क वापस लिए जाने की स्थिति में पाटन की संभावना है तथा पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने का स्वयं ही औचित्य बनाते हैं।

ब.2 निर्यातकों का अनुरोध

83. सीमा शुल्क तथा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, क्षति के बार-बार होने की कोई संभावना नहीं है।
- i. याचिकाकर्ताओं ने चीनी उत्पादकों के पास अत्यधिक क्षमता उपलब्ध होने तथा उनके भारत को निर्यात किए जाने की संभावना के ब्यौरे नहीं दिए हैं याचिकाकर्ता पाटन की संभावना का मामला बनाने में विफल रहे हैं।
 - ii. यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वर्तमान जाँच में घरेलू उद्योग को क्षति की कोई संभावना नहीं है और वर्तमान जाँच रद्द किए जाने योग्य है।

ब. 3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

84. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II(vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों पर विचार करते हुए, क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना की जाँच की। घरेलू उद्योग ने चीनी सीमा शुल्क के अनुसार चीन के तीसरे देशों को निर्यातों के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं जो दर्शाते हैं कि तीसरे देशों को *** प्रतिशत निर्यात मात्रा उस कीमत से कम कीमत पर है जिस पर चीन भारत को निर्यात करता है और तीसरे देशों को *** प्रतिशत निर्यात मात्रा उस कीमत से अधिक कीमत पर है जिस पर चीन भारत को निर्यात करता है।
85. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों तथा उनके अनुरोधों के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार किया है। प्राधिकारी ने निम्नलिखित शीर्षों के तहत क्षति के जारी रहने और बार-बार होने की संभावना की जाँच की है:
- क. पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयात की संभावना दर्शाते हुए भारत में पाटित आयातों की बढ़े हुए आयात की काफी दर।
- ख. किसी अतिरिक्त निर्यात को लेने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य, अथवा आसन्न, भारतीय बाजार में पर्याप्त रूप से बढ़े हुए पाटित आयातों की संभावना दर्शाते हुए निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि।
- ग. क्या आयात उन कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर काफी न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव होगा तथा और आयातों के लिए मांग बढ़ने की संभावना होगी।
- घ. जाँच की जा रही वस्तु की मालसूची।
86. पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयात की संभावना दर्शाते हुए भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की काफी दर

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जाँच की अवधि
चीन	मी. टन	4,356	1,930	2205	2969
अन्य	मी. टन	79	115	30	65
कुल आयात	मी. टन	4,434	2,045	2,235	3,034

* अप्रैल, 17 से मार्च, 18

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में आयातों की मात्रा में सतत गिरावट थी।
88. सहयोगी उत्पादकों के लेन-देन वार आंकड़ों का उनके संबंधित निर्यातकों के साथ विश्लेषण वर्तमान जाँच के सहयोगी उत्पादकों के पाटित और क्षतिकारक आयातों को निकालने के लिए निम्नलिखितानुसार है:

क) मैसर्स एन्क्यु लु एन फार्मास्युटिकल कं.लि .

उपर्युक्त उत्पादक द्वारा संबद्ध सामानों के व्यापारी के साथ भारत में कुल निर्यात *** मी. टन हैं जिनमें से *** मी. टन पाटित आयात हैं और *** मी. टन क्षतिकारक आयात हैं।

ख) मैसर्स लियानयुंगांग कंगले फार्मास्युटिकल कं.लि .

संबद्ध सामानों के उपर्युक्त उत्पादक द्वारा अपने निर्यातकों के माध्यम से भारत में कुल निर्यात *** मी. टन हैं जिनमें से पाटित आयात *** मी. टन हैं। उपर्युक्त उत्पादक के उसके निर्यातक के माध्यम से कोई क्षतिकारक आयात नहीं पाए गए।

ग) मैसर्स हेबेई जिहेंग .लि .फार्मास्युटिकल कं (ग्रुप)

संबद्ध सामानों के उपर्युक्त उत्पादक द्वारा भारत को कुल निर्यात ***मी. टन है। उपर्युक्त उत्पादक के सभी आयात पाटिल हैं और *** मी. टन क्षतिकारक हैं।

- (ख) किसी अतिरिक्त निर्यात को लेने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य, अथवा आसन्न, भारतीय बाजार में पर्याप्त रूप से बढ़े हुए पाटित आयातों की संभावना दर्शाते हुए निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि।

89. प्राधिकारी ने उत्तरदाता निर्यातकों के पास मौजूदा अधिशेष क्षमताओं, क्षमता अभिवृद्धि, यदि कोई है, भारत को तीसरे देशों से व्यापार बदलने की संभावना, उत्तरदाता निर्यातकों के पास स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य उत्पादन क्षमताओं का मूल्यांकन किया। विश्लेषण निम्नलिखित दर्शाता है:

क. क्षमता, उत्पादन, अधिशेष क्षमताएं, भारत को निर्यात तथा शेष विश्व को निर्यात, भारत को निर्यात की मात्रा

उत्पादक का नाम	यूनिट	एन्क्यू लु एन फार्मास्युटिकल कं. लि.	लियानयुंगांग कंगले फार्मास्युटिकल कं. लि.	हेबेई जिहेंग (ग्रुप) फार्मास्युटिकल कं. लि.	कुल
क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
उत्पादन (जाँच की अवधि)	मी. टन	***	***	***	***
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
घरेलू खपत	मी. टन	***	***	***	***
भारत को निर्यात	मी. टन	***	***	***	***
आरओडब्ल्यू को निर्यात	मी. टन	***	***	***	***
कुल निर्यात	मी. टन	***	***	***	***
निर्यातोन्मुख %	रेंज %	***	***	***	35-45

ख. सहयोगी निर्यातकों की क्षमताओं के विश्लेषण के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों और सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों की क्षमताएं

क्रम सं.	चीन में उत्पादक	क्षमता (मी. टन प्रति वर्ष)
1.	अनहुई बीबीसीए लिकेंग फार्मास्युटिकल	10,000
2.	चांगशू हुआगेंग फार्मास्युटिकल	8000
3.	जियांग्सु वर्ल्ड काइंडली फार्मास्युटिकल	10000
4.	वेनझोऊ फार्मास्युटिकल्स फैक्ट्री	6,000
5.	जियांग्सू गुओहेंग फार्मा केमिकल्स कं. लि.	2,500
6.	रुंकी ट्रेडिंग कं. लि.	12,000
7.	शंघाई बैलियन केमिकल्स कं. लि.	50,000
8.	लियानोयुआन सिटी बैकांग फार्मास्युटिकल	500
9.	गैर-असहयोगी कंपनियों की कुल क्षमता	99,000
10.	असहयोगी उत्पादकों की कुल क्षमता	75,000
11.	चीन जन. गण. की कुल क्षमता	174,000
12.	भारतीय मांग	51,069

ग. तथापि, सहयोगी उत्पादकों के विश्लेषण यह देखा जाता है कि व्यापारिक कंपनियों के पास उनकी अपनी उत्पादन सुविधाएं नहीं हैं और वे अपनी वेबसाइट पर उत्पादकों की क्षमता का उल्लेख करते हैं।

घ. उत्तरदाता उत्पादकों के क्षमता उपयोग और निर्यातोन्मुखता तथा घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए साक्ष्य पर विचार करते हुए यह सिद्ध है कि चीन में अधिशेष क्षमताएं हैं और चीनी उत्पादक निर्यातोन्मुख हैं।

(ग) जाँच की जा रही वस्तु की मालसूची

90. चीनी उत्पादकों द्वारा दायर किए गए प्रश्नावली के उत्तर यह दर्शाते हैं कि सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के पास मालसूची का स्तर काफी अधिक है।

उत्पादक	यूनिट	2015	2016	2017	जाँच की अवधि
मैसर्स एन्क्यू लु एन फार्मास्युटिकल कं. लि.	मी. टन	***	***	***	***
लियानयुंगंग कंगला फार्मास्युटिकल कं. लि.	मी. टन	***	***	***	***
हेबेई जिहेंग (ग्रुप) फार्मास्युटिकल कं. लि.	मी. टन	***	***	***	***
कुल	मी. टन	***	***	***	***

(घ) भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता

91. चीन जन. गण. से शेष विश्व को निर्यात के संबंध में चीन जन. गण. सीमा शुल्क के आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने से चीनी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए भारत में उनके निर्यात बढ़ाने के लिए भारतीय कीमतें आकर्षक होंगी और वह निम्नलिखित तालिका से निकाला जा सकता है।

देश	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य अमेरिकी डॉलर	कीमत अमेरिकी डॉलर/किग्रा.
भारत (आईएन)	***	***	***
कांगो, डीआर	***	***	***
क्यूबा (सीयू)	***	***	***
केन्या (केई)	***	***	***
मॉरीशस (एमयू)	***	***	***
इंडोनेशिया (आईडी)	***	***	***
दक्षिण अफ्रीका (जेडए)	***	***	***
ईराक (आईक्यू)	***	***	***
जंबिया (जेडएम)	***	***	***
रूस (आरयू)	***	***	***
ईरान (आईआर)	***	***	***
सीरियन (एसवाई)	***	***	***
बेनिन (बीजे)	***	***	***
मोजांबिक (एमजेड)	***	***	***
संयुक्त अरब अमीरात (एई)	***	***	***
तंजानिया (टीजेड)	***	***	***
लुथियानिया (एलटी)	***	***	***

श्रोत: चीनी सीमा शुल्क

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि तीसरे देशों को *** प्रतिशत कुल निर्यात मात्रा उस कीमत से कम कीमत पर है जिस पर चीन भारत को निर्यात करता है। जबकि *** प्रतिशत कुल निर्यात उस कीमत से अधिक कीमत पर निर्यात किए जाते हैं जिस पर चीन भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात करता है।

(ड) चीन जन. गण. में निर्यातोन्मुखता

93. चीनी सीमा शुल्क के आंकड़ों और घरेलू उद्योग द्वारा दायर अन्य साक्ष्य के अनुसार प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन में निर्यातक वैश्विक रूप से निर्यात के प्रति उन्मुख हैं।

पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में यह संभावना है कि निर्यातक/उत्पादक भारत में संबद्ध सामानों के पाटन का सहारा लेंगे।

अ. कारणात्मक संपर्क और अन्य ज्ञात कारकों का योगदान न होने का विश्लेषण

94. सतत पाटन की मौजूदगी, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के मात्रात्मक और कीमत प्रभाव की जाँच करने के बाद भारतीय नियमावली और पाटनरोधी करार के तहत सूचीबद्ध अन्य संकेतात्मक मानदंडों की प्राधिकारी द्वारा यह देखने के लिए निम्नलिखित रूप में जाँच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा एवं कीमत

95. संबद्ध देश को छोड़कर अन्य देशों से आयातों का विवरण यह दर्शाता है कि अन्य देशों से संबद्ध सामानों के आयात न्यूनतम स्तर से कम पर आ रहे हैं। अतः अन्य देशों से आयातों को घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले नहीं माना जा सकता।

ख. मांग में संकुचन और/वर्तनअथवा खपत के पैटर्न में परि

96. संबद्ध सामानों के लिए समग्र मांग ने क्षति की अवधि में सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है। यह भी नोट किया जाता है कि खपत के पैटर्न में कोई पर्याप्त परिवर्तन प्राधिकारी की जानकारी में नहीं आया है, न ही किसी हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई अनुरोध किया है।

ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां तथा विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्द्धा

97. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां नहीं हैं जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो क्योंकि कच्ची सामग्री तथा संबद्ध सामान देश में स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हैं। घरेलू उद्योग एक-दूसरे से प्रतिस्पर्द्धा करते हैं और साथ ही संबद्ध सामानों के आयातों से प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।

घ. प्रौद्योगिकी में विकास

98. संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी में विकास को घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाला कारक नहीं माना जा सकता।

ड. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

99. घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। तथापि, घरेलू और निर्यात बाजार में कीमत और लाभप्रदता को वर्तमान क्षति मूल्यांकन के लिए प्राधिकारी द्वारा अलग-अलग किया गया है। अतः निर्यात निष्पादन ने इस विवरण में प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण को प्रभावित नहीं किया होता।

च. अन्य उत्पादों का निष्पादन

100. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन का संबद्ध उत्पाद के सूचित किए गए निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामानों के निष्पादन की जाँच की है। अतः घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित किए जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

अ. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात अनुरोध

101. प्राधिकारी द्वारा विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों को भेजे गए पत्रों के लिए अनुरोध और उसके संबंध में दायर किए गए उत्तरों की प्रतियों के प्रकटन के लिए अनुरोध, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर किए गए पत्रों, प्रत्युत्तर अनुरोधों,

सत्यापन रिपोर्ट, सामान्य मूल्य, एनआईपी के विवरण तथा क्षति विश्लेषण में वास्तविक आंकड़े। यदि कोई चीज गोपनीय है तो याचिकाकर्ता ने उसके अगोपनीय रूपांतर का अनुरोध किया है।

102. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पैरा 63 में नोट किया है कि आयात मात्रा 2015-16 तक कम हुई है और उसके बाद बढ़ी है। तथापि, यह अनुरोध किया जाता है कि 2015-16 में आयात की मात्रा में गिरावट आई है और उसके बाद लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद उसमें कोई वृद्धि हुई है।
103. जहां तक मैसर्स ग्रैन्यूल्स इंडिया का संबंध सूचना प्रदान न करने के संबंध में है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि मैसर्स ग्रैन्यूल्स इंडिया किसी विक्रेता के साथ कोई विशेष व्यवस्था के साथ काफी निर्यात कर रहा है और इसीलिए उस सीमा तक उसका उत्पादन बाजार में उपलब्ध भी नहीं है। कंपनी को इस सीमा तक कोई क्षति नहीं हो रही है।
104. उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता जैसे आर्थिक मानदंडों में लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण सुधार हुआ है।
105. प्राधिकारी द्वारा किए गए पाटित और क्षतिग्रस्त आयातों के परिकलन के अनुसार पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता है।
106. जब घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई नहीं पाई गई है, तो क्षति मार्जिन के परिकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी को संभावित क्षति के आधार पर जाँच परिणाम जारी करने चाहिए और उसी मात्रा में शुल्क जारी रखना चाहिए, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा विगत में विभिन्न मामलों में किया गया था।
107. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 में घरेलू उद्योग को संभावित पाटन और संभावित क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क स्थापित करने की अपेक्षा नहीं है। वह शुल्क की समाप्ति पर पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के सबूत से संबंधित है।
108. निर्धारित क्षति रहित कीमत बहुत कम है जिसके परिणामस्वरूप नकारात्मक क्षति मार्जिन है। क्षति रहित कीमत कारकों की संख्या के कारण कम हुई है। घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वह कृपया नियोजित पूंजी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें।
109. नियोजित पूंजी अचल परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य अथवा अचल परिसंपत्तियों के कम से कम सकल मूल्य पर विचार करते हुए निर्धारित की जानी चाहिए। किसी भी दशा में निवल अचल परिसंपत्तियों को लेना अत्यधिक अनपुण्य है और वस्तुतः यह विचार करते हुए घरेलू उद्योग के लिए अनुचित है कि कुछ निवेश काफी पुराने हैं तथा इसीलिए निवल अचल परिसंपत्तियां निवेश का सही मूल्य नहीं दर्शातीं। वस्तुतः इस प्रयोजन के लिए सबसे अधिक उचित मूल्य निवेशों का वर्तमान मूल्य है।
110. कटोच कमेटी रिपोर्ट, 145वीं संसदीय रिपोर्ट और भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और औषध विभाग द्वारा जारी 18 अप्रैल, 2018 के कार्यालय ज्ञापन जैसे दस्तावेजों में व्यक्त किए गए अनुसार भारत सरकार के दृष्टांत का हल नहीं किया गया है।
111. जिस अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है, वह संगत नहीं है और कानून के तहत ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि कोई विशेष मामला, विशेष मामले की श्रेणी में आना चाहिए, यदि शुल्क 10 वर्ष से अधिक बढ़ाया जाना हो। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ब्राजील जैसे वैश्विक प्राधिकारियों ने 30 वर्ष से भी अधिक शुल्क बढ़ाया है।
112. घरेलू उद्योग वर्तमान में पाटित आयातों से क्षति के लिए सुभेद्य है। संबद्ध देश से आयात मात्रा और पाटन मार्जिन के वर्तमान स्तर स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि शुल्क की समाप्ति से संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का गहन पाटन होगा।
113. चूंकि, लगभग 86 प्रतिशत वैश्विक उत्पादन भारत और चीन में ही है और जिसमें से 62 प्रतिशत उत्पादन अकेले चीन में है जबकि भारत का शेष 24 प्रतिशत हिस्सा है। इस प्रकार, इस उद्योग में किसी रुग्णता से वैश्विक मांग चीनी उत्पादकों की दया और एकाधिकार पर ही रह जाएगी।
114. शुल्क के अपर्याप्त स्वरूप के प्रतिकूल प्रभाव के कारण देश में भारी पैमाने पर उत्पादन लंबित रहा जो प्रमुख रूप से पिछले दो दशकों में रहे (ये सभी बंदियां 5 वर्षों से अधिक की हैं और पाटनरोधी शुल्क को पूर्व में बनाए जाने से पूर्व के हैं)।

115. पैरासिटामॉल के निर्माण के कीमतें डीपीसीओ और एनपीपीए के तहत शामिल हैं। अतः उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। पैरासिटामॉल अधिक लागत वाली औषधि नहीं है और इसीलिए किसी भी दशा में उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के किसी संभावित प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में कोई चिंता नहीं होनी चाहिए।

ट. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

116. फिक्की रिपोर्ट जैसी अन्य बाजार सूचना और एपीआई के संबंध में, भारत सरकार के दृष्टांत पर वर्तमान जाँच में निष्कर्षों के लिए मार्गदर्शी हथियार के रूप में विचार नहीं किया जाना चाहिए।
117. वर्तमान जाँच में मालसूची का विश्लेषण औसत मालसूची के बजाए बिक्री/उत्पादन की प्रतिशतता के रूप में आधार बनाया जाए।
118. चूंकि, परिकलित कीमत कटौती पाटनरोधी शुल्क के बिना पहुँच मूल्य पर आधारित है, यदि पाटनरोधी शुल्क कीमत कटौती के स्तर में शामिल किया जाता है तो काफी अधिक आ जाएगी। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि शुल्क की वापसी के मामले में घरेलू उद्योग को क्षति की कोई संभावना नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग की पहले ही घरेलू बाजार में उच्चतर कीमतें हैं और चीन से निर्यातों की कीमतें शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में नीचे नहीं आने वाली हैं। यह भी अनुरोध है कि प्रकटन विवरण में अग्रिम लाइसेंस जैसी विभिन्न शुल्क मुक्त स्कीमों के तहत भारत में संबद्ध सामानों के आयातों का कोई विश्लेषण नहीं है कि उन्हें घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने के लिए कैसे माना जा सकता है।
119. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में पाटन या क्षति किसी के भी होने की संभावना नहीं है।
120. चूंकि, चीन से सभी निर्यातों के लिए नकारात्मक क्षति मार्जिन है, अतः घरेलू उद्योग को क्षति की कोई संभावना नहीं है।
121. सहयोगी उत्पादकों की अकेले मालसूची का प्रयोग क्षति और संभावित विश्लेषण के लिए मार्गदर्शी कारक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता।
122. भारतीय बाजार सहयोगी निर्यातकों के लिए कीमत आकर्षक नहीं है।
123. चीनी सीमा शुल्क के आंकड़े भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बहुत सुदूर हैं। कीमत आकर्षकता का विश्लेषण सहयोगी निर्यातकों द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर दिया जाना चाहिए।
124. घरेलू उद्योग द्वारा निर्यातों की मात्रा पर कारणात्मक संपर्क विश्लेषण करते समय विचार किया जाना चाहिए।

ठ. प्राधिकारी द्वारा जाँच

125. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटन पश्चात टिप्पणियां अधिकतर दोहराई गई हैं। तथापि, प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई टिप्पणियों का नीचे उल्लेख किया गया है :-

- (क) जहां तक प्राधिकारी से अधिक सूचना के प्रकटन के लिए अनुरोध का प्रश्न है जैसे कि सामान्य मूल्य, एनआईपी विस्तृत विश्लेषण और क्षति विश्लेषण में वास्तविक आंकड़े, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकट की गई सूचना नियमों और प्राधिकारी के पिछली प्रथाओं के पूर्ण अनुसरण में है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अंतर्गत सभी अनिवार्य तथ्यों को प्रकट किया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी अगोपनीय दस्तावेजों को सभी हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण के लिए सार्वजनिक फाइल में रखा गया था।
- (ख) जहां तक घरेलू उद्योग के अनुरोध का संबंध है कि निर्धारित क्षति रहित कीमत बहुत निम्न है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एन आई पी सत्यापित आंकड़ों और प्राधिकारी के सुसंगत अभ्यास के आधार पर नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है।
- (ग) जहां तक भारत सरकार के मत का संबंध है, जैसा कि कटोच समिति की रिपोर्ट, 145वीं संसदीय रिपोर्ट और भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्युटीकल विभाग द्वारा जारी दिनांक 18 अप्रैल, 2018 के कार्यालय ज्ञापन जैसे दस्तावेजों में व्यक्त किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच नियमों, मामले के तथ्यों और प्राधिकारी की पिछली प्रथाओं के अनुसार आयोजित की गई थी।

- (घ) जहां तक एनआईपी कीमत के निर्धारण का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि एन आई पी को जाँच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना और कंपनी के लेखापरीक्षित आंकड़ों व तथ्यों के समुचित सत्यापन/लेखा समाधान के पश्चात घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। निवल निर्धारित परिसंपत्ति को निरपवाद रूप से परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य के आधार पर अपनाया गया है जिसमें सभी पाटनरोधी जांचों में अनुसरण की जा रही पद्धति के अनुसार पुनर्मुल्यांकन और दिए गए उपचार का प्रभाव शामिल नहीं है।
- (ङ) जहां तक इस निवेदन का प्रश्न है कि विभिन्न शुल्क मुक्त स्कीमों जैसे अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातों का कोई विश्लेषण नहीं किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसका यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयात के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- (च) जहां तक चीन और भारत के बीच वैश्विक उत्पादन को दो भागों में बांटे जाने और घरेलू उद्योग की वर्तमान स्थिति का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसके क्षति विश्लेषण के अनुसार, संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उद्योग का उत्पादन भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

ड. निष्कर्ष

126. किए गए दावों, उपलब्ध कराई गई सूचना और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्य, जैसे कि इस अंतिम जाँच परिणाम में दर्ज किए गए हैं, प्राधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि :-

1. रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य यह इंगित नहीं करते कि चीन से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
2. चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयात पूरी क्षति अवधि के दौरान नगण्य बने रहे हैं।
3. यदि वर्तमान ए. डी. डी. की विद्यमानता को समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग क्षति की संभावना के संबंध में अपने दावे को प्रमाणित करने में असफल रहा है।
4. घरेलू उद्योग ने सभी क्षति संबंधी मानदंडों की शर्तों में सुधार दर्शाया है और घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग द्वारा किया गया संबद्ध वस्तु का उत्पादन भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
5. जहां तक संबद्ध वस्तुओं का संबंध है, प्राधिकारी द्वारा कीमत आकर्षकता का विश्लेषण, चीनी निर्यातों के लिए भारत को कीमत आकर्षण के रूप में स्थापित नहीं करता।
6. ए. डी. डी. सितंबर, 2001 के बाद से लागू था और घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ है। इस प्रकार, ए. डी. डी. ने अपने अभिप्रेत उद्देश्य को पूरा कर लिया है।

ढ. सिफारिश

127. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच आरंभ की गई थी और इस संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध और पाटनरोधी अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों की शर्तों में लागू ए.डी.डी. को समाप्त किए जाने के पश्चात पाटन की संभावना में जाँच को आरंभ तथा आयोजित करते हुए प्राधिकारी ने माना

है कि घरेलू उद्योग इस संबंध में कोई संतोषजनक साक्ष्य उपलब्ध कराने में असफल रहा है कि ऊपर बताए गए कारणों और/अथवा दिए गए विश्लेषण के अनुसार उक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के कारण पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। इसलिए, प्राधिकारी चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश नहीं करते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

NOTIFICATION

New Delhi, 29th January, 2019

FINAL FINDINGS

Subject: Sunset Review of the anti-dumping duty on imports of Paracetamol originating in/exported from China PR

1. **F. No. 7/16/2018-DGAD.**— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) had recommended imposition of anti-dumping duty on imports of “Paracetamol” (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country).
2. Whereas, the original investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority vide Notification No. 60/1/2000 – DGAD dated 30th January, 2001. The Preliminary Findings were issued by the Authority vide Notification No. 60/1/2000-DGAD dated 16th April, 2001 and the provisional antidumping duty was imposed by the Department of Revenue vide Notification No. 89/2001 Customs dated 6th September, 2001. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide notification No. 60/1/2000-DGAD dated 22nd January 2002, recommending imposition of definitive duty. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed by the Department of Revenue vide Notifications No. 29/2002 Customs dated 27th March, 2002 on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country. 1st Sunset Review was concluded and Authority had issued the Final Findings in the Sunset Review vide Notification No. 15/20/2006-DGAD dated 23rd July 2007 and fixed duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 99/2007 -Customs dated 3rd Sept, 2007. 2nd Sunset Review was concluded and Authority had issued the Final Findings in the Sunset Review vide Notification No. 14/1009/2012-DGAD –dated 26th August 2013 and fixed duty was imposed by the Central Government vide Notification No 26/2013-Customs dated 28 October, 2013.
3. Whereas, in terms of Section 9A(5) the Customs Tariff Act, 1995, read with Rule 23 of the Rules, the anti-dumping duty imposed under the said Act shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, unless in a review, initiated before the expiry of the duty, the Designated Authority concludes that the cessation of the duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
4. And, notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of expiry of the measure as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
5. Whereas, the petition was filed by M/s Farmson Pharmaceuticals Gujarat Private Limited and M/s Sri Krishna Pharmaceuticals Limited (hereinafter referred to as Petitioners) and was supported by M/s Bharat Chemicals, M/s Granules India Ltd., and M/s Meghmani Unichem LLP in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of sunset review investigation of the Anti-Dumping Duty concerning imports of Paracetamol originating in and exported from China PR.

6. In view of the duly substantiated application with prima facie evidence of likelihood of dumping and injury filed on behalf of the Domestic Industry and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority issued a Notification. No. 07/16/2018-DGAD dated 24th May, 2018, published in the Gazette of India, initiating a Sunset Review investigation to review the need for continued imposition of the duties in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The validity of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject country was extended by the Central Government up to 24th May 2019 vide Notification No. 39/2018-Customs (ADD) dated 20th August, 2018.
7. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

A. GENERAL PROCEDURE

8. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation:
 - i. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
 - ii. The Authority issued a public notice dated 24th May, 2018 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating Sunset Review investigation of anti-dumping duty investigation concerning imports of Paracetamol originating in and exported from China PR
 - iii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the embassy of China PR in India, known producers/exporters from China PR, known importers/users and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days from the date of communication in accordance with the Rules 6(2) & 6(4).
 - iv. The Authority provided copy of the non-confidential version of the application to the known exporters/producers and the embassy of the subject country in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non- confidential version of the application was also made available in the form of a public file and provided to other interested parties, wherever requested.
 - v. The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in China PR, (whose details were made available by the applicant) and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules:
 - a) Anhui Bayi Chemical Industry Co. Ltd.
 - b) Anhui Fubore Pharmaceutical
 - c) Zhejiang Kangle Pharmaceutical Co.
 - d) M/s Wenzhou Pharamaceuticals factory
 - e) Changshu Huagang Pharmaceutical Co. Ltd.
 - f) Hebei Jiheng Group Co. Ltd.
 - g) Jiangsu World Kindly Pharmaceuticals Ltd
 - h) Jiangsu Guoheng Pharma Chemical Co. Ltd.
 - i) Shanghai Bailion Chemicals Co. Ltd.
 - j) Lianoyuan City Baikang Pharmaceutical
 - k) Runqi Trading Co. Ltd.
 - l) AnqiuLu'an Pharamaceutical Co Ltd
 - vi. The following producers/exporters have filed the Exporter questionnaire response :-
 - a) M/s Anqiu Lu An Pharmaceutical Co., Ltd.
 - b) M/s A.H.A International Co., Ltd.
 - c) China Sinopharm International Corporation
 - d) Zhejiang Chemcials Import and Export Corporation
 - e) Lianyungang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd.
 - f) Zhejiang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd.
 - g) Hebei Jiheng (group) Pharmaceutical Co. Ltd.

- vii. Supplementary questionnaire was also forwarded to the known producers/exporters in China PR and the embassy of China PR in India with the request to provide relevant information to the authority within the prescribed time limits.
- viii. However, none of the exporters has filed the Supplementary questionnaire.
- ix. The Authority sent a copy of the Initiation Notification along with Importer's Questionnaires to the following known importers/users/user associations (whose names and addresses were made available to the Authority) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 6(4).:
 - a) Aura Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
 - b) Shalina Laboratories Pvt. Ltd.
 - c) Medicamen Biotech Ltd.
 - d) Adcock Ingram Ltd.
 - e) Sanofi India Ltd.
 - f) Fourrts (India) Laboratories Pvt Ltd.
 - g) Indoco Remedies Ltd.
 - h) Astra Lifecare (India) Pvt. Ltd.
 - i) J.B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.
 - j) Unilink Pharma Pvt. Ltd.
 - k) Medopharm
 - l) Milan Laboratories (India) Pvt. Ltd.
 - m) Agog Pharma Ltd.
 - n) Combitic Global Caplet Pvt. Ltd.
- x. However, no questionnaire response has been received from any importer of the subject goods.
- xi. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6 (7).
- xii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis and the same were kept in the public file maintained by the Authority as per the Rules
- xiii. The Authority has examined the information furnished by the domestic producer to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III to work out the cost of production and the Non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xiv. Period of Investigation in the present investigation is 01st April 2017- 31st March 2018. The injury investigation period is April 2014-March15, April 2015-March16 and April 2016-March17 and the Period of Investigation (POI).
- xv. Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the Domestic Industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
- xvi. Transaction wise data was called from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) & DG Systems. The Authority has relied on DGCI&S data and the data of co-operative exporters for calculating volume and value of imports of the subject goods in India.
- xvii. The Authority held an oral hearing on 29th August, 2018 to provide an opportunity to all the interested parties to present relevant information orally in accordance to Rule 6 (6). The interested parties who had presented their views in the oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally. The interested parties were provided opportunity to offer rejoinder submissions to the views expressed by the opposing interested parties. The Authority has considered submissions received from all the interested parties appropriately.
- xviii. Exporters, producers and other interested parties who have neither responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation have been treated as non-cooperating interested parties.

- xix. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xx. *** in this disclosure statement represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxi. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$ = Rs. 65.33

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

B.1 Submissions by the Domestic Industry

9. The following are the submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article:-
 - i. The scope of the product under consideration under the present investigation is "Paracetamol also known as acetaminophen" as determined by the Authority in previous investigations. Paracetamol is an organic chemical and is classified under Custom sub-heading 2922.2933 of the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
 - ii. Paracetamol is a white powder. Its chemical formula is C₈H₉NO₂. Paracetamol is a common analgesic and antipyretic drug that is used for the relief of fever, headache and other minor aches and pains. It is a major ingredient in numerous cold and flu medications and many prescription analgesics.
 - iii. The present investigation being a Sunset Review investigation and antidumping duties, as earlier recommended by the Authority, being in force on the imports of the subject goods from the subject country, the Authority should consider that the scope of the PUC in the present investigation remains the same as that of the earlier investigations.

B.2 Submissions by the exporters/importers/other interested parties

10. None of the other interested parties have raised any issues with regard to the product under consideration.

B.3 Examination by Authority

11. The product under consideration in the present Sunset Review investigation is Paracetamol. Paracetamol is classified under Customs sub heading No 2922.2933 under chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975. However, customs classification is indicative in nature and not binding on the scope of the investigation.
12. The Product under consideration as defined in the previous investigations is as follows :-

"The product under consideration, in the original as well as the 1st SSR investigation and the present sunset review investigation, is "Paracetamol also known as acetaminophen", originating in or exported from China PR. The present investigation being a sunset review, the investigation covers the product covered in the original investigation as well as the 1st SSR investigation".
13. The present investigation being a Sunset Review investigation and antidumping duties, as earlier recommended by the Authority, being in force on the imports of the subject goods from the subject country, the Authority considers that the scope of the PUC in the present investigation remains the same as that of the earlier investigations. Moreover, none of the interested parties has made any submission in this regard.
14. Therefore the authority has considered PUC as under :-

The product under consideration, in the previous investigations as well as the present sunset review investigation, is "Paracetamol also known as acetaminophen", originating in or exported from China PR. The present investigation being a sunset review, the investigation covers the product covered in the original investigation.

"Paracetamol is an odourless white crystalline powder. Its chemical formula is C₈H₉NO₂. Paracetamol is a bulk pharmaceutical active ingredient, displaying analgesic and antipyretic properties. It is used in a number of Rx and OTC drug formulations in the form of powders, granules, injectibles and tablets. Paracetamol is an organic

chemical and is classified under Custom sub-heading 2922.2933 of the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.”

C. LIKE ARTICLE

C.1 Submissions by the Domestic Industry

15. The domestic industry has claimed that there is no known difference in subject goods exported from subject country and that produced by the Indian industry. Both the products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications and tariff classification etc.

C.2 Submissions by the exporters/importers/other interested parties

16. None of the interested parties have disputed the claims made by the domestic industry in this regard.

C.3 Examination by Authority

17. The Authority notes from the information available on record that the product under consideration produced by the Domestic Industry is like article to the goods imported from the subject country. Product under consideration produced by the Domestic Industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications and tariff classification of the goods. It is further noted that the Designated Authority had examined the issue of product under consideration and like article in the previous investigations, which mutatis mutandis is relied upon in the present review investigation. The goods produced by the Domestic Industry and imported from the subject country are like articles in terms of the Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Submissions by the Domestic Industry

18. The domestic industry has made the following submissions:-

- i. The Petition for review and continuation of the anti-dumping duty in force on imports of Paracetamol originating in or exported from China PR has been filed by M/s Farmson Pharmaceuticals Gujarat Private Limited and M/s Sri Krishna Pharmaceuticals Limited and was supported by M/s Bharat Chemicals, M/s Granules India Ltd., and M/s Meghmani LLP.
- ii. The Petitioners other than M/s Sri Krishna pharmaceutical have not imported the product under consideration. M/s Sri Krishna pharmaceuticals Ltd have imported merely 30 MT, which is insignificant in relation to its production, Indian production and Indian demand.
- iii. Petitioners command a major proportion in Indian production and accordingly constitute “domestic industry” within the meaning of the Rules.
- iv. Petitioner is not related, either directly or indirectly, to any exporter or importer of product under consideration in the subject country. Thus, the petitioner is an eligible Domestic Industry under Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

D.2 Submissions by the exporters/importers/other interested parties

19. The interested parties have made the following submissions:-

- i. The levy of the anti-dumping duty is dependent upon the dumping margin and there is no such principle of granting sufficient protection to the domestic industry in the anti-dumping investigations.
- ii. There are significant changes in the composition of the domestic industry in all the four investigations concerning the product under investigation before the Authority as may be seen from the following:-
 - a) Original Investigation: It may be seen that in the original investigation before the Authority, there were four producers namely M/s Triton Laboratories Ltd., M/s Vamsi Labs Ltd., Srinivasa Agro Industries & Drugs Ltd. and Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd. who participated in the investigation and provided injury information.
 - b) First Sunset Review: In first sunset review there were three producers namely, Sri Krishna Pharmaceuticals, M/s Farmson Analgesics Pvt. Ltd and M/s Bharat Chemicals Ltd.

- c) Second Sunset Review: In the second SSR, Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd. and M/s Bharat Chemicals Ltd. provided injury information.
 - d) Third Sunset Review-Present Investigation: In the current investigation, again only the 2 producers namely Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd. and M/s Farmson Analgesics Pvt. Ltd. have been participating and provided injury information.
 - e) The composition of the domestic industry or the domestic producers in all the four investigations are different and it is not difficult to assume that the composition of the domestic producers was changed at their will and desire to suit their needs,
 - f) It may be seen that the domestic producers who were petitioners in the previous investigations i.e. original investigation and the two sunset review investigations have not provided any information in the present case
 - g) There is no analysis or reasons in the petition as to why those producers who were petitioners in the earlier investigations are not providing information in the current investigation.
 - h) In the initiation notification also, there is no analysis with respect to those producers not providing information.
 - i) M/s Triton Laboratories Ltd. was merged with Granules India Ltd. in the year 1998. However, M/s Triton Laboratories Ltd. was projected as a separate company from Granules India Ltd. In spite of the fact that the former was merged with the later at the time of initiation of original investigation i.e. on 30th January 2001 and no company with the name of Triton Laboratories existed at the time of initiation of original investigation. However, the domestic producers forming part of the domestic industry at the time of original investigation misled the Authority and got the anti-dumping duties imposed by misrepresenting the facts in the original investigation.
 - j) M/s Granules India Ltd. in the first sunset review investigation was shown as an importer and not included as part of the investigation. M/s Granules India Ltd. is the largest producer of subject goods in India. It has sales of Rs. 579 Crores in the POI.
 - k) The domestic industry has not provided the injury information of M/s Granules India Ltd despite it being the largest company.
 - l) Even in the previous two sunset reviews investigations, no injury information was obtained from M/s Granules India Ltd. for a meaningful analysis and conclusions in those investigations. There are no reasons in the petition or in the initiation notification as to why this producer has not provided information in the present investigation when the amalgamated company of Granules India i.e. Triton Laboratories participated in the original investigation as a petitioner and provided injury information.
- iii. M/s Farmson Analgesics Pvt. Ltd. is also one of the largest producers of the subject goods in India. It was a petitioner in the first sunset review and not a petitioner in the second sunset review. With regard to this producer also, there are no reasons in the petition or in the initiation notification as to why this producer has not provided information in the 2nd sunset review and is now providing injury information in the present investigation.
- iv. The producers who were also the petitioners in the previous investigations commanding majority of the production have not provided injury information in the current investigation and only the producers with a limited and low share in the total domestic production have provided injury information, there is no ground for the continuation of the duties in the current investigation as in each investigation the sufficient injury information of the domestic industry has been kept away from the examination.
- v. The present case is a fit case for termination of investigation and discontinuation of the duties.

D.3 Examination by the Authority

20. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers.”

21. The petition has been filed by M/s Farmson Pharmaceuticals Gujarat Private Limited and M/s Sri Krishna Pharmaceuticals Limited and was supported by M/s Bharat Chemicals, M/s Granules India Ltd., and M/s

Meghmani LLP. Post initiation, one of the supporting companies namely M/s Bharat Chemicals has provided all the necessary information. However, the Authority has not considered the same as it was filed at belated stage of investigation.

22. In the present case, the producers before the Designated Authority have output constituting a major proportion of the total domestic production and thereby the legal requirement as stipulated in Rule 2 (b) of the AD rules is met. However, in case of Sunset review it would be desirable to have the same composition of domestic industry as in original investigation.
23. The Authority notes, on the basis of information on record that the production of Applicants constitutes a major proportion of total Indian production. Among the petitioners M/s Sri Krishna pharmaceuticals Ltd. has imported merely *** MT of PUC during POI, which is ****% in relation to its production and ****% in Indian demand, which is very insignificant and therefore the Authority has considered them as an eligible domestic industry while initiating the present investigation. Also, the Authority had satisfied itself of the adequacy and accuracy of the data submitted by the petitioner by an onsite visit. Further, the petitioners are related neither to an importer in India nor to any exporter from subject country. Thus, the petitioner companies are eligible domestic industry in terms of AD Rules. Further, production of the petitioner companies constitutes “a major proportion of total Indian production” and hence, satisfies the standing requirements for the subject goods under Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules.

E. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY

E.1 Submissions by the domestic industry

24. The domestic industry has made the following submissions:-
- The exporter/ producers have made unnecessary claims as to confidentiality or provided incomplete information thereby handicapping the domestic industry in making meaningful comments with regard to the responses filed. The responses are not properly indexed or summarized.
 - Information provided in non-confidential version is beyond understanding. The NCV does not provide clear understanding of the data and the domestic industry is unable to provide detailed comments on that for the same reason.
 - Non-confidential version of the questionnaire responses is grossly inadequate and incomplete. The concerned interested party has not disclosed all such information that they are obligated to disclose under the Rules and practice being followed by the Designated Authority in this regard.

E.2 Submissions by the exporters/importers/other interested parties

25. The exporters/importers/other interested parties have made the following submissions:-
- The petitioners have claimed excessive confidentiality without providing any legitimate reasons in violation of Rule 7 of the Customs and Tariffs Rules, 1995. The Petitioners have not disclosed the following information in their petition:-
 - Soft Copy in excel file of transaction-wise and sorted import data, raw/original import data and list of excluded transactions from DGCI&S has not been provided.
 - The import data has not been provided for the whole POI and has been provided only for the 9 months.
 - The item-wise details of constructed normal value have been kept as confidential,
 - Company-wise production details of the petitioners, supporting producers and the domestic producers have been kept as confidential.
 - The annual report of the companies for the POI and the previous three years have not been provided. The domestic industry has simply stated that the same may be seen from the website of the petitioners. However, it may be seen that there are no annual reports available on the website of the petitioners.
 - In the application, it has been mentioned that Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd. has imported the subject goods. However, the reasons have not been provided by the domestic industry.
 - The domestic industry has claimed adjustment from export price for ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, inland transportation, commission and VAT adjustment. However, no evidence with regard to the aforesaid adjustments claimed have been provided by them,

- i. Profit/ loss and ROCE in percentage terms have been kept confidential,
- j. The Hon'ble Authority may kindly direct the petitioners to disclose and provide the aforesaid information so as to enable the exporters/ producers for making effective comments in this investigation.

E.3 Examination by the Authority

26. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

"7. Confidential information:-

(1) Notwithstanding anything contained in sub rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

27. Submissions made by the interested parties with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are examined and addressed accordingly. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the need for treating them as confidential. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims of all the parties and accordingly not disclosed such information to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide non-confidential summary of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties in the form of public file.

F. Miscellaneous Submissions

F.1 Submissions by the domestic industry

28. The exporter questionnaire filed by responding exporter/ producers namely M/s Anqiu Lu An Pharmaceutical Co., Ltd., Zhejiang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd, M/s A.H.A International Co., Ltd., Zhejiang Chemicals Import & Export Corporation, and China Sinopharm International Corporation are deficient in nature and none of them have filed the exporter Questionnaire Response (Part2), which seeks information from the exporters on their capacities, capacity expansion, transaction wise third country exports, domestic sales, inventories etc. These details/information are indicative of likelihood behaviour of the exporters and therefore they are required to be submitted to the Authority in the Sunset Review investigation. It is submitted that, this is not a case of deficient information but complete failure to file the required information in the prescribed format itself.
29. The production of product under consideration is quite limited globally. As, about 86% of global production is in India and China only and out of which 62% of the production is in China alone, while India commands the remaining 24%. Thus, any sickness in this industry would leave the Indian users at the mercy and monopoly of the Chinese producers.
30. That due to the adverse effect of the insufficient form of duty there were large-scale production suspension in the country, which was primarily in the last two decades (all these closures are more than 5 years old and are prior to previous extension of ADD).
31. As per 145th Parliamentary standing committee on commerce which assessed the impact of Chinese goods on Indian industry, it is clearly stated that API sector needs protection from import and the government of India also endeavors to revive the API sector in India.
32. Katoch Committee Report dated 24 September, 2015 on Active Pharmaceuticals Ingredients (APIs) specifically states that a long term strategy for strengthening API sector by involving Ministry of Commerce as well as other regulatory authorities is required which involves judicious and liberal use of measures like anti-dumping.

33. FICCI report February 2018 edition on “Trends and Opportunities for Indian Pharma” highlights that dependence on China for API supplies exposes the pharma industry to raw material supply disruptions and price volatility.
34. Office Memorandum dated 18 April, 2018 issued by the Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Pharmaceuticals, constituted a Task force to formulate a roadmap for enhanced production of API s in the country as there is need for concerted efforts to harness the opportunities in pharmaceutical sector.
35. The public at large is already well protected through a regulatory mechanism as Paracetamol is covered under National List of essential medicine in Pharmaceutical Policy, 2015.
36. Paracetamol is one of the cheapest API available in the country.

F.2 Submissions by the exporters/importers/other interested parties

37. None of the other interested parties has made any submissions.

F.3 Examination by the Authority

38. The Authority notes that Exporter Questionnaire Response (Part2), which seeks information from the exporters on their capacities, capacity expansion, transaction wise third country exports, domestic sales, inventories etc were later filed by the co-operative exporters/producers. The non-confidential versions of the said responses were kept in public file so as to facilitate their access to other interested parties.

The Authority takes note of the evidence filed by the Applicants as to the stance of Government of India with regard to API and other market information such as the report of FICCI.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

39. The Authority sent questionnaire to known exporters from subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed. The following producers and exporters from the subject country filed the questionnaire response:-
 - i. M/s Anqiu Lu An Pharmaceutical Co., Ltd.
 - ii. M/s A.H.A International Co., Ltd.
 - iii. China Sinopharm International Corporation
 - iv. Zhejiang Chemicals Import and Export Corporation.
 - v. Lianyungang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd.
 - vi. Zhejiang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd.
 - vii. Hebei Jiheng (group) Pharmaceutical Co. Ltd.
40. According to Section 9A (1) (c) of the Customs Tariff Act, 1975 ‘Normal Value’ in relation to an article means: -

“comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin”.

G.1 Views of the Domestic Industry

41. The following are the submissions made by the domestic industry, during the course of present investigation and considered relevant by the Authority:-

- i. China needs to be treated as non-market economy for the reason that the costs and prices in China do not reasonably reflect the market forces. Para 8 to Annexure-I specifies the parameters which should be considered for grant of market economy status. This also implies that unless these conditions are not fulfilled/satisfied, the Chinese costs and prices cannot be adopted.
- ii. Chinese producers are required to be treated as companies operating under non-market economy environment and the Authority may proceed to determine the normal value on the basis of Para 7 of Annexure-I.
- iii. The imports are entering the Indian market at dumped prices.
- iv. There is difference in prices in different import transactions which mean that Chinese producers are selling very same product at a price which differs significantly even at the same time period and is not a peculiar phenomenon of POI, but extends to the entire injury period,
- v. It is a fit case where weighted average normal value cannot be compared with weighted average export price. The Designated Authority is, therefore, requested to compute the weighted average normal value and compare the same with individual export price and in all those import transactions where the dumping margin is negative, the same are required to be excluded for determination of dumping margin.
- vi. There can be no plausible reason/justification for such significant difference in the prices in respect of imports being reported at the same time.

G.2 Views of the interested parties

42. The submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties are as follows:-

- i. Determination of the normal value for subject country in the current investigation as computed by the domestic industry is not in accordance with the legal provisions and therefore, the determination of dumping margin in the current investigation by the petitioners is flawed.
- ii. Normal value for the companies in China PR in the current investigation may please be determined on the basis of their domestic sales and the cost of the subject goods.
- iii. It is in view of the fact that the period of 15 years for disregarding the domestic prices or costs of Chinese producers not being on market economy conditions as provided in para 15(a)(ii) of the Protocol of Accession of the People's Republic of China to WTO, has expired on 11th December 2016 in terms of para 15 (d) and has become non-operational.
- iv. At present, no provisions which enable the Hon'ble Authority for considering Chinese producers as operating on non-market economy principles for disregarding their domestic prices and costs and the normal value for China may be determined on the basis of their domestic prices and cost of the subject goods.
- v. Any other methodology used for the determination of normal value for Chinese exporters would be in violation of the obligations of India under the WTO.
- vi. Without prejudice to above submission it is submitted that determination of normal value for Chinese exporters on the basis of their records without following any additional procedure, domestic industry has arbitrarily determined the normal value for Chinese exporters without following the due procedure as laid down under the Indian Anti-dumping Rules.
- vii. The constructed normal value proposed by the domestic industry is based on the cost of production in India and considering the rate of profit at 5%. However, the item-wise cost details of the constructed normal value have not been provided.
- viii. The methodology of relying upon the Indian costs and prices is to be followed only when it was not possible to construct the normal value on the basis of other alternatives prescribed in the opening sentence of Para 7.
- ix. In terms of the provisions of Para 7, the market economy third country is required to be first identified for determination of normal value and only where it is not possible to obtain necessary data from such third country, the normal value can be determined on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin.

- x. The domestic industry is under obligation to inform, without reasonable delay the selection of market economy third country to the parties concerned so as to provide an opportunity to respond to the same.
- xi. Mandatory procedure prescribed by the law has not been followed, as the interested parties have not been put to notice about selection of the third country. Nor have the interested parties been requested to suggest and make necessary information available about the third country.
- xii. In the absence of following the mandatory procedure, the present proceeding cannot continue in view of the decision of the Hon'ble Supreme Court in the case of Shenyang Matsushita 2005 (181) ELT 320 (SC).
- xiii. The failure to follow the mandatory procedure of Para 7 has substantive implications on the determination of the normal value and resultantly the dumping margin.
- xiv. Therefore, the Hon'ble Authority is requested to follow the procedure prescribed in Para 7 of the Annexure I in the current investigation.

G.3 Examination by the Authority

a. Normal Value in China

- 43. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of normal value. The Authority sent copies of the Supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting presumption of nonmarket economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the AD Rules. The Authority also requested Government of China to advise the producers/exporters in their country to provide the relevant information. However, none of the Chinese producers filed any response to the Supplementary questionnaire issued by the Authority.
- 44. Accordingly, the normal value and export price for all the producers/exporters from the subject country have been determined as below:

b. Determination of Normal Value for producers and exporters in China PR

- 45. As none of the producers from China PR have filed the Supplementary Questionnaire response, the normal value has been determined in accordance with Para 7 of Annexure I of Anti-Dumping Rules. In the absence of sufficient information on record regarding the other methods as are enshrined in Para 7 of Annexure I of the AD rules, the Authority has determined the normal value by adopting the method "any other reasonable basis".
- 46. The Authority has, therefore, constructed the normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses. Accordingly, the constructed normal value for Chinese exporters is determined **Rs. ******* per Kg.

c. Determination of export price of China PR

- 47. The Authority notes that exporters mentioned below from China PR have furnished information to the Authority, which was used for determination of export price and individual dumping margin.
 - i. M/s Anqiu Lu An Pharmaceutical Co., Ltd.
 - ii. M/s A.H.A International Co., Ltd.
 - iii. China Sinopharm International Corporation
 - iv. Zhejiang Chemicals Import and Export Corporation
 - v. Lianyungang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd.
 - vi. Zhejiang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd.
 - vii. Hebei Jiheng (group) Pharmaceutical Co. Ltd.

In view of the responses filed, the Authority has analysed the response made by the producers /exporters as follows:-

M/s Anqiu Lu An Pharmaceutical Co., Ltd.(producer)and M/s A.H.A International Co., Ltd., China Sinopharm International Corporation and Zhejiang Chemicals Import and Export Corporation

- 48. The Authority notes that M/s Anqiu Lu An Pharmaceutical Co., Ltd. has exported *** MT of the subject goods directly to India and *** MT through its traders M/s A.H.A International Co., Ltd., China Sinopharm International Corporation and Zhejiang Chemicals Import and Export Corporation. The Authority notes that whereas Anqiu Lu An Pharmaceutical Co has reported an export price of US\$ ***/MT and A.H.A International Co., Ltd., China Sinopharm International Corporation and Zhejiang Chemicals Import and Export Corporation have reported net export price of US\$ ***, US\$ ***/MT and US\$ ***/MT respectively.

49. The producers-exporters have claimed price adjustments on account of inland freight, ocean freight, and marine insurance, credit cost, port expenses and VAT. Ex-factory export price has been determined for each producer/exporter. Weighted average export price of the said producer and its respective traders have thereafter been determined as US\$ *** /MT considering the total volume of exports made by the said exporter.

M/s Lianyungang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd. (producer) and M/s Zhejiang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd.

50. The Authority notes that M/s Lianyungang Kangle Pharmaceutical Co. has exported *** MT through its trader namely M/s Zhejiang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd. They have claimed price adjustments on account of inland freight, ocean freight, marine insurance, credit cost, port expenses and VAT. After adjustment of the expenses claimed by the producer/trader, the authority has determined the ex-factory export price as US\$ *** /MT.

M/s Hebei Jiheng (group) Pharmaceutical Co. Ltd. (producer).

51. The Authority notes that M/s Hebei Jiheng (group) Pharmaceutical Co. Ltd have exported *** MT directly to India. The exporters have claimed price adjustments on account of inland freight, ocean freight, marine insurance, credit cost, port expenses and VAT. After adjustment of the expenses claimed by the producer/trader accordingly, the authority has determined the ex-factory export price as ***** US\$/MT.

d. Determination of Dumping Margin

52. The dumping margin during the POI for all exporters/producers from the subject country has been determined as provided in the table below:-

Name of company (Producer) (POI)	Name of the company (Exporter)	CNV US\$/MT	NEP US\$/MT	Dumping margin US\$/MT	DM %	Range
M/s Anqiu Lu An Pharmaceutical Co., Ltd.	M/s A.H.A International Co., Ltd.	***	***	***	***	0-10
	China Sinopharm International Corporation					
	Zhejiang Chemicals Import and Export Corporation					
Lianyungang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd.	Zhejiang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd.	***	***	***	***	0-(10)
Hebei Jiheng (group) Pharmaceutical Co. Ltd.		***	***	***	***	10-20

e. Determination of Dumping Margin for China PR as a whole.

- a) Comparing the normal value and export price at ex-factory level for the country as a whole, the dumping margin for the subject country is determined as below:

Particulars US\$/Kg -Rs./Kg. (POI)	US\$/Kg.	Rs./Kg.
Normal Value	***	***
Net Export Price	***	***

Dumping Margin	***	***
Dumping Margin %	***	***
Range %	10-20	10-20

- b) After detailed analysis of DGCIS transaction wise data it has been observed that out of total imports of China PR i.e.*** MT *** % imports are dumped and *** % are injurious.

H. INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1 Submissions by the Domestic Industry

53. Following are the submissions made by the Domestic Industry: -

- i. Nature of sunset review is different than that of original investigation as the focus is more on likelihood of the continuation or recurrence of dumping and injury, in case antidumping duties are removed. Presence of current injury or presence of current dumping is not required to be examined for the review cases where likelihood of injury is more important.
- ii. With respect to the injury determination, if the anti-dumping duty has had the desired effect, the condition of the domestic industry is expected to have improved during the period the anti-dumping duty was in force.
- iii. The assessment whether injury will continue, or recur, would entail a counter-factual analysis of future events, based on projected levels of dumped imports, prices, and impact on domestic industry.
- iv. The Designated Authority has to address the question as to whether the domestic industry is likely to be materially injured again, if duties are lifted.
- v. There is negative price undercutting. This is due to anti-dumping duty in force; the situation is likely to reverse in the event of cessation of anti-dumping duty.
- vi. There had been an increase in selling price and the landed price of imports due to anti-dumping duty in force. In the event of cessation of anti-dumping duty, the imports in all likelihood would have price suppression and depression effect.
- vii. Production, capacity utilization and sales of the domestic industry have increased. However, should the present duties cease at this stage, the capacity utilization shall decline significantly.
- viii. Profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry have increased since the base year.
- ix. Market share of the domestic industry and other Indian producers has remained constant throughout the investigation period. In the event of cessation of anti-dumping duty, the dumped imports from subject country will resume in significant volumes taking away market share of the domestic industry.
- x. The growth of the domestic industry in terms of most of the parameters has shown improvement. This is due to anti-dumping duty in force. The situation is likely to reverse in the event of cessation of anti-dumping duty.
- xi. In the present case, export price from subject country significantly differs in terms of time period and therefore it is a fit case where weighted average normal value cannot be compared with weighted average export price.
- xii. The Designated Authority is requested to consider weighted average normal value and compare with individual export price and in all those import transactions where the dumping margin is negative, the same are required to be excluded for determination of dumping margin.
- xiii. The period for which duty has been in force is irrelevant for determining whether there is a need for continuation of duties. The law provides for extension of duties if the cessation of such duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping or injury. Even as per the practice of other countries such as Canada, USA, Brazil and European Union, duties may continue to be in force for more than 15 years, even if there are no imports of the subject goods.

H.2 Submissions by the exporters/importers/other interested parties

54. Following are the submissions made by the exporters.

- i. There is no injury to the domestic industry in the current investigation and all the injury parameters of the domestic industry have significantly improved over the injury investigation period.
- ii. The anti-dumping duties against the import of subject goods are in existence for more than 17 years and the present case is not a special case where duties are required to be extended for a further period of 5 years.

- iii. The majority of imports to India from subject country are under duty free schemes such as advance license, DEPB etc. run by the Govt. of India which are not subject to duty.
- iv. Even if such imports are included for analysis of injury and likelihood of injury and anti-dumping duty is recommended, the imports made under said duty free schemes would not be subject to any anti-dumping duty and would continue to come to India
- v. The composition of the domestic industry in all four investigations before the Hon'ble Authority has significantly changed. Therefore, there are no reasons to believe that the domestic industry is being currently affected.
- vi. The largest producer of the subject goods i.e. Granules India having sales of Rs. 579 Cores in the period of investigation in India have been abstained from all the 3 sunset review investigations and provided no injury information. Therefore, the analysis of injury and likelihood of injury on the basis of limited information in all the 3 SSR investigations cannot give the true picture of the state of the domestic industry and therefore, in the current case, there is no need to extend duty for another period of five years.
- vii. The Authority while issuing the Final Finding concerning Dry Cell Batteries from China PR (Case No. 15/2/2011-DGAD & Final Findings dated 20th May 2013) has held that the anti-dumping duties beyond 10 years be imposed in Special cases only.
- viii. In case there is increase in imports from subject country after the anti-dumping duty is not extended, the domestic industry can always file application for initiation of fresh anti-dumping investigation.

H.3 Examination of the Authority

- 55. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.
- 56. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules.
- 57. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
- 58. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
- 59. In consideration of submissions received in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.

(i) Assessment of Demand/ Apparent Consumption

- 60. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the subject goods in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The

demand for the product under consideration is given below:-

**April 17 to Mar18*

Demand	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
Indexed		100	104	108	108
Sales of Other Indian Producers	MT	***	***	***	***
Indexed		100	114	108	110
Imports from					
China	MT	4,356	1,930	2205	2969
Other Countries	MT	79	115	30	65
Total Demand	MT	48,251	50,295	49,603	50,770

61. The Authority notes that the demand has shown increase over the injury period, even though it had marginally declined in 2016-17 as compared to the preceding year. The demand increased once again in the period of investigation as compared to both the preceding year and base year.

(ii) Volume Effect of Dumped Imports and impact on Domestic Industry: Import volume and Market Share.

62. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The table below summarizes the factual position with regard to import volumes and market share:-

Particulars	Units	2014-15	2015-16	2016-17	POI
China	MT	4,356	1,930	2205	2,969
Other Countries	MT	79	115	30	65
Total imports	MT	4,434	2,045	2235	3034
Market Share in Demand					
Sale of Domestic Industry	%	***	***	***	***
Sale of other Indian Producers	%	***	***	***	***
Import from subject country	%	9%	3.8%	4.44%	5.84%
Import from other countries	%	0.16%	0.22%	0.06%	0.11%
Total Demand	%	100	100	100	100

63. It is seen that the import volume declined till 2015-16 and increased thereafter. Also, the market share in demand of the domestic industry has remained more or less constant.

(iii) Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

a. Price Undercutting

64. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports when compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The Authority has compared landed price of imports with the selling price of the domestic industry for the subject goods.

Price Undercutting

Particulars	Unit	POI
Landed price of imports from China PR	Rs./Kg.	250.06
Net Sales Realization	Rs./Kg.	***
Price undercutting	Rs./Kg.	(***)

Price undercutting	%	(***)
Range		(0-10)

From the above, the Authority notes that there is no price undercutting.

65. The domestic industry submitted and opposing interested parties have not disputed that the entirety of the imports were made under advance license and therefore neither customs duty nor ADD was paid on these imports.

a. Price Suppression/ Depression

66. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:-

Particular	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Cost of sales	Rs. /Kg.	***	***	***	***
Trend		100	89	87	99
Selling price	Rs. /Kg.	***	***	***	***
Trend		100	93	89	103
Landed price of imports	Rs./Kg.	265	266	238	250
Trend		100	102	87	94

67. The Authority notes that whereas the selling price has increased in the POI as compared to the base year, the cost of sales has marginally declined in POI. The landed value of imports from subject country has declined in POI as compared to the base year. The Authority notes that the domestic industry increased its selling price in proportion to increase in cost of sales throughout the injury period. Therefore, there is no price suppression or depression.

(iv) Economic Parameters of the Domestic Industry

68. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.
69. Accordingly, various economic parameters of the Domestic Industry are analyzed herein below:-

a) Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales Volume

70. Production, sales, capacity & capacity utilization details are as follows:-

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	111	126
Capacity utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	111	126
Domestic Sales for PUC	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	116	117

From the above information, the Authority notes the following:-

- a) Capacity of the domestic industry has remained constant over the period.

b) The production, sales and capacity utilization of the Domestic Industry has increased over the injury period.

b) Demand

Demand	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
Indexed		100	104	108	108
Sales of Other Indian Producers	MT	***	***	***	***
Indexed		100	114	108	110
Imports from					
China	MT	4,356	1,930	2205	2969
Others	MT	79	115	30	65
Total Demand	MT	48,251	50,295	49,603	50,770

71. From the above information it is noted that

i) Sales of DI and other Indian producers have increased from the base year.

ii) Imports from China PR and other countries have declined from the base year despite increase in total demand during the same period.

c) Market Share in Demand

72. The details of market share of the Domestic Industry in demand are given in table below.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Sale of Domestic Industry	%	***	***	***	***
Sale of other Indian Producers	%	***	***	***	***
Import from subject country	%	9%	3.8%	4.44%	5.84%
Import from other countries	%	0.16%	0.22%	0.06%	0.11%
Total Demand	%	100	100	100	100

73. It is seen that the market share of Domestic Industry has marginally increased over the injury period.

a. Profitability, return on investment and cash profits

74. Performance of the Domestic Industry with regard to profits, return on investment and cash flow is as follows: -

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Profit/(Loss)	Rs./ Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	375	225	325
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	240	165	255
Return on Capital Employed- NFA	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	173	90	136

75. It is seen from the above table that the profitability, cash profits and return on investments have increased in the POI when compared to the base year.

a. Inventories

76. Inventories with the Domestic Industry are as follows:-

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Average	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	110	125	130

77. It is noted that the average inventory level of the subject goods has shown an increasing trend.

a. Employment, Productivity and Wages

78. Performance of the Domestic Industry with regard to employment, productivity and wages is as follows:-

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
No of Employees	Nos	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	110	118	119
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	104	138	168
Productivity/person/Day	Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	94	94	106

79. It is seen from the above that the number of employees, wages and productivity during POI have increased as compared to the base year.

I. Magnitude of Injury and injury margin

80. The Non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during the POI and the injury margin so worked out is as under.

SN	Particular	UOM	China (POI)
1	Import Volume	MT	2969
2	Non Injurious Price	Rs/KG	***
3	Landed Price	Rs/KG	***
4	Injury Margin	Rs/KG	(***)
5	Injury Margin	%	(***)
	Injury Margin RANGE		0-(10)

J. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

81. As this is a Sunset Review investigation and the authority now examines the likely scenario of continued dumping and consequent injury if the anti-dumping duties were allowed to expire.

J.1 Submissions by the Domestic Industry

82. Following are the submissions made by the Domestic Industry with regard to likelihood of continuation of dumping and consequent recurrence of injury –

- i. A perusal of Article 11.1 of AD Agreement and Section 9A (5) of the Customs Tariff Act, clearly suggests that the main intent behind the legislation of Sunset Review investigation is to examine: -
 - a) Whether the dumping continued and if so, whether it is likely to continue;
 - b) In case where dumping did not continue, whether the dumping would recur in the event of revocation of anti-dumping duties;
 - c) Whether the Domestic Industry continued to suffer injury; and if so, whether injury to the domestic industry is likely to continue;
 - d) In case where the Domestic Industry has not suffered continued injury, whether injury to the Domestic Industry is likely to recur in the event of revocation of anti-dumping duties.
- ii. The original investigation and the subsequent Sunset Review investigations also established the existence of significant dumping. The dumping margin in the previous as well as the first SSR was quite high.
- iii. There is a long history of dumping of subject goods from China in domestic market as well as in other countries such as South Africa and Indonesia.
- iv. The continued dumping was only reduced after the last concluded sunset review investigation. Prior to that, the domestic industry was suffering continued injury on account of significant dumped imports, as stated by the Authority in the final findings earlier notified in the review cases.

- v. The significant level of these imports only started declining since 2015-16. However, it is pertinent to note that the domestic industry is still healing from the past injurious effects of dumping and thus is in a vulnerable state. Cessation of anti-dumping duties is likely to cause intensified injury to the domestic industry.
- vi. It would appear that the domestic industry has enjoyed antidumping duty protection for the last 15 years, the fact is that the domestic industry has been effectively protected for only last five years. The Chinese producers continued dumping and the same caused injury to the domestic industry for one decade, despite the ADD being in force.
- vii. The change in the form of duty from benchmark to fixed quantum has led to reduction in imports. Cessation of antidumping duty is likely to increase the imports as significant surplus capacities are available with the producers. The decline in the imports is because of existence of ADD.
- viii. Due to continuous dumping, several plants producing the PRODUCT UNDER CONSIDERATION have been closed down in the country namely:-
- M/s Triton Laboratories Ltd.
 - M/s Vamsi Labs Ltd.
 - M/s Srinivasa Agro Industries & Drugs Ltd.
 - M/s Pan Drug
 - M/s Alpha Drug
 - M/s Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd.
 - M/s Thexa Pharma Pvt. Ltd.
 - M/s Vani Pharma Labs Ltd.
 - Rohini Chemical
 - Fortune Chemical
 - Dinesh Pharmaceutical
 - Dr. Jain's Company
 - Saboo Medichem
- ix. The production of product under consideration is quite limited globally. About 86% of global production is in India and China. 62% of the production is in China alone, while India commands 24%. Thus, any sickness in this industry would leave the global demand at the mercy of the Chinese producers.
- x. The questionnaire responses filed by the exporters, establish that there is import of subject goods from subject country at dumped price.
- xi. The domestic industry in the present scenario is still reeling from the adverse effects of the dumping and has shown marginal growth in terms of its economic parameters. The same growth would be reversed if the Anti-dumping duty is ceased by the Authority.
- xii. The only reason the domestic industry has not suffered further deterioration in its performance is that the volume of imports was low due to the duties in force. However, the producers in the subject country have significant idle capacities, which are sufficient to meet the entire demand in India. In the event of cessation of duty, the exports are likely to utilize these unutilized capacities and flood the Indian market.
- xiii. The foreign producers are export oriented, in as much as their capacities are far more than the domestic demand in the subject country. The production of the subject goods in subject country is in the range of 1 lac MT, as against 2.21 lac MT capacities; whereas the domestic demand for the product in China is far lower nearly 20,000 MT. This clearly shows that the exporters have built up capacities in excess of the demand in the subject country out of 1 lac MT production, about 80% are meant for exports.
- xiv. The exporters have not only been dumping in India, but also in other countries. Further, the prices at which the goods have been supplied to these countries are lower than the non-injurious price. It is therefore, reasonable to conclude that the exporters are likely to sell at dumped and injurious prices in India as well in case the duty is revoked.
- xv. The export price from subject country to various countries globally are far lower than the export price to India in respect of significant proportion of exports from subject country to various countries globally. The dumping margin and injury margin in these third countries exports are higher than the dumping margin and injury margin in respect of exports to India.

- xvi. Since India is a more price attractive market as compared to third countries, the exporters would prefer to divert their goods from other countries to India in case of revocation of duty, in order to increase their profits and capture the market. Considering that the exporters have no commitments in these third country markets and the sole criteria for them to price their product is price received by them.
- xvii. Decline in imports post imposition of duty and positive dumping margin in such imports implies likelihood of dumping in the event of withdrawal of duty and in itself justifies extension of anti-dumping duty.

J.2 Submission of exporters

83. There is no likelihood of recurrence of injury as per Article 9A (5) of the Customs and Tariffs Act.

- The petitioners have not given the details of excessive capacity available with the Chinese producers and their likelihood of being exported to India, the petitioners have failed to make out a case of likelihood of dumping.
- This clearly indicates that there is no likelihood of injury to the domestic industry in the current investigation and the present investigation deserves termination.

J.3 Examination by the Authority

84. The Authority examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the Anti-dumping Rules. The domestic industry has submitted the details of exports of China to third countries as per China customs which shows that ***% volume of exports to third countries are at a price lower than price at which China exports to India and ***% of the volume of exports to third countries are at a price above than price at which China exports to India.
85. The Authority has taken into consideration the submissions made by the domestic industry and the evidence presented in support of their submissions. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury under following heads:
- A significant rate of increase importation; of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.
 - Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
 - Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
 - Inventories of the article being investigated.
86. **A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.**

Particulars	Units	2014-15	2015-16	2016-17	POI
China	MT	4,356	1,930	2205	2969
Others	MT	79	115	30	65
Total imports	MT	4,434	2,045	2,235	3,034

**April 17 to Mar18*

87. The Authority notes that there was a consistent decline in the volume of imports compared to base year.
88. An analysis of transaction wise data of the cooperative producers with their respective exporters so as to arrive at dumped and injurious imports of the cooperative producer of the present investigation is as follows: -

a) M/s Anqiu Lu An Pharmaceutical Co., Ltd.

The total exports to India by the said producer with trader of the subject goods are *** MT out which *** MT are dumped imports and *** MT are injurious imports.

b) M/s Lianyungang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd

Total exports to India by the said producer of the subject goods through its exporters is *** MT out which dumped imports constitute ***MT. No injurious imports were found for the said producer through its exporter.

c) **M/s Hebei Jiheng (group) Pharmaceutical Co. Ltd**

Total exports to India by the said producer of the subject goods is *** MT. All imports of the said producer are dumped and *** MT are injurious.

(b) Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.

89. The Authority evaluated the existing surplus capacities, capacity addition, if any, with the responding exporters, possibility of trade diversion from third countries to India, freely disposable production capacities with the responding exporters. The analysis shows as follows:

a. Capacity, production, surplus capacities, exports to India and rest of the world, volume of exports to India

Name of Producer	Units	Anqiu Lu An Pharmaceutical Co., Ltd.	Lianyungang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd.	Hebei Jiheng (group) Pharmaceutical Co. Ltd.	Total
Capacity	MT	***	***	***	***
Production (POI)	MT	***	***	***	***
Capacity utilisation	%	***	***	***	***
Domestic Consumption	MT	***	***	***	***
Exports to India	MT	***	***	***	***
Exports to ROW	MT	***	***	***	***
Total Exports	MT	***	***	***	***
% Exports Orientation	Range %	***	***	***	35-45

b. After analysis of the capacities of the cooperative exporters, the Authority notes that the capacities of the following non-cooperative exporters/producers as per the data submitted by the petitioner and the information available in public domain.

S. no	Producers in China	Capacity (MT per annum)
1.	Anhui BBKA Likang Pharmaceutical	10,000
2.	Changshu Huagang Pharmaceutical	8000
3.	Jiangsu World kindly Pharmaceutical	10000
4.	Wenzhou Pharmaceuticals factory	6,000
5.	Jiangsu Guoheng Pharma chemicals Co., Ltd.	2,500
6.	Runqi trading Co., Ltd	12,000
7.	Shanghai Bailion Chemicals Co., Ltd	50,000
8.	Lianoyuan City Baikang Pharmaceutical	500
9.	Total capacity of non-co-operative entities	99,000
10.	Total capacity of cooperative producers	75,000
11.	Total capacity of China PR	174,000
12.	Indian demand	51,069

c. However, it is observed from the analysis of the cooperating producers that the trading companies do not have their own production facilities and they quote the capacity of the producers on their websites.

d. Considering the capacity utilisation and export orientation of the responding producers and evidence provided by the domestic industry, it is evident that there are surplus capacities in China and the Chinese producers are export oriented.

(C) Inventories of the article being investigated

90. The questionnaire response filed by the Chinese producer's shows that level of inventories with the cooperative producers/ exporters is quite significant.

Producer	Units	2015	2016	2017	POI
M/s Anqiu Lu An Pharmaceutical Co., Ltd.	MT	***	***	***	***
Lianyungang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd.	MT	***	***	***	***
Hebei Jiheng (group) Pharmaceutical Co. Ltd.	MT	***	***	***	***
Total	MT	***	***	***	***

(D) Price attractiveness of Indian market

91. Analysis of the China PR Custom data with regard to export from China PR to the rest of the world. indicate that with the revocation of ADD, the Indian prices would be attractive for the Chinese producers/Exporters to increase their exports to India and the same can be deduced from the table given below:

Country	Quantity (kg)	Value USD	Price USD/kg
India (IN)	***	***	***
Congo,DR	***	***	***
Cuba (CU)	***	***	***
Kenya (KE)	***	***	***
Mauritius (MU)	***	***	***
Indonesia (ID)	***	***	***
S. Africa (ZA)	***	***	***
Iraq (IQ)	***	***	***
Zambia (ZM)	***	***	***
Russia (RU)	***	***	***
Iran (IR)	***	***	***
Syrian (SY)	***	***	***
Benin (BJ)	***	***	***
Mozambique (MZ)	***	***	***
United Arab Emirates (AE)	***	***	***
Tanzania (TZ)	***	***	***
Lithuania (LT)	***	***	***

Source : China Custom

92. The Authority notes that *** % total volume of exports to third countries is at a price lower than the price at which China exports to India. Whereas ***% of the total exports are exported are above the price at which China exports the subject goods to India.

(E) Export Orientation of China PR

93. As per the data of China Customs and other evidence filed by the Domestic Industry, the Authority notes that the producers in China are oriented towards exports globally.

In the event of cessation of ADD, there is probability that the exporters/producers would resort to dumping of subject goods to India.

K. CAUSAL LINK AND NON ATTRIBUTION ANALYSIS OF OTHER KNOWN FACTORS

94. Having examined the existence of continued dumping, volume and price effects of dumped imports on the prices of the Domestic Industry, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-Dumping have been examined herein below by the Authority to see whether any other factor, other than the dumped imports could have contributed injury to the Domestic Industry.

a. Volume and price of imports from third country:

95. Statement of imports from countries other than the subject country shows that the imports of subject goods from other countries are entering at below de minimis level. Therefore, the imports from other countries cannot be considered to have caused injury to the Domestic Industry

b. Contraction in Demand and / or Changes in Pattern of Consumption

96. Overall demand for the subject goods has shown positive growth during the injury period. It is also noted that no significant change in the pattern of consumption has come to the knowledge of the authority, nor any interested party has made any submission in this regard.

c. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

97. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the Domestic Industry as the raw materials as well as the subject goods are freely importable in the country. The Domestic Industry competes among one another and at the same time competes with the imports of the subject goods.

d. Development in technology:

98. Technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, development in technology cannot be regarded as a factor causing injury to the domestic injury.

e. Export performance of the Domestic Industry:

99. Domestic Industry has exported the subject goods. However, the price and profitability in the domestic and export market has been segregated by the authority for the purpose of present injury assessment. Therefore, export performance would not have affected the injury analysis made by the Authority in this statement.

f. Performance of other products:

100. Performance of other products being produced and sold by the Domestic Industry has no impact over the reported performance of the subject product as the Authority has examined the performance of the subject goods only. Therefore, no injury has been suffered by the domestic industry on account of the performance of other products being manufactured by domestic industry.

L. Post Disclosure submissions by the Domestic Industry

101. A request for disclosure of communication sent by the Authority to various interested parties and copies of replies filed thereof, communication filed by interested parties, rejoinder submissions, verification report, normal value, NIP breakdown and actual data in injury analysis. In case there is anything confidential, petitioner has requested non confidential version of the same.
102. Designated Authority at Para. 63 has noted that the import volume declined till 2015-16 and increased thereafter. However, it is submitted that there is a decline in the volume of import in 2015-16 and thereafter it increased significantly despite Anti-dumping duty in force.
103. As regards M/s Granules India not providing information, the domestic industry has submitted that M/s Granules India is undertaking significant exports with some special arrangements with some buyer and therefore its production to that extent is not even available in the market. The company is not suffering injury to such an extent.
104. Economic parameters such as production, sales, capacity utilization, profitability of the domestic industry has improved because of Anti-dumping duty in force.

105. As per the calculation of dumped and injured imports done by the Authority, there is need for continuation of Anti-dumping duty.
106. When no injury is found to have occurred to the Domestic Industry, there is no need for computation of injury margin. Accordingly, the Authority should issue finding on the basis of likelihood analysis and continue the same quantum of duty as was done by the Authority in various cases in the past.
107. Article 11.3 of the Anti-dumping Agreement does not require the establishment of causal link between the likely dumping and likely injury to domestic industry. It deals with proof of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, if the duty expires.
108. The non-injurious price determined is too low resulting into negative injury margin. The non-injurious price has been reduced on account of number of factors. The domestic industry requests the authority to kindly consider the followings with regard to Capital Employed.
109. Capital employed should be determined considering present value of fixed assets, or at the least gross value of fixed assets. In any case, adoption of net fixed assets is highly inappropriate and, in fact, unfair to the domestic industry, considering that some of the investments are significantly old and therefore net fixed assets does not represent true value of investments. In fact, the most appropriate value for the purpose is present value of the investments.
110. The stance of Government of India as expressed in documents such as Katoch Committee report, 145th Parliamentary report and Office Memorandum dated 18 April, 2018 issued by the Government of India, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Pharmaceuticals has remained unaddressed.
111. Period for which anti-dumping duty is imposed is not relevant and there is no requirement under law that a particular case should fall under the category of a special case if the duty is to be extended beyond ten years. Furthermore, global authorities such as the USA, Canada, and Brazil have extended the duty even for 30 years.
112. Domestic Industry is vulnerable to injury from dumped imports at present. Current levels of import volumes and dumping margins from the subject country clearly shows that expiry of duty will result in intensified dumping of subject goods from the subject country.
113. As, about 86% of global production is in India and China only and out of which 62% of the production is in China alone, while India commands the remaining 24%. Thus, any sickness in this industry would leave the global demand only at the mercy and monopoly of the Chinese producers.
114. Due to the adverse effect of the insufficient form of duty there were large scale production suspension in the country which were primarily in the last two decades (all these closures are more than 5 years old and are prior to previous extension of ADD).
115. Paracetamol formulation prices are covered under DPCO and NPPA therefore no adverse effect on the consumers. Paracetamol is not a high cost medicine and therefore in any case there should be no concern with regard to possible adverse impact of the ADD on the consumers.

M. Post Disclosure Comments by other interested parties

116. Stance of Government of India with regard to API and other market information such as FICCI report should not be considered as a guiding tool for the conclusions in the current investigation.
117. Analysis of inventory in the current investigation may be based as percentage of sales/ production instead of average inventory.
118. As the price undercutting calculated is based on landed values without ADD, if the ADD is included the level of price undercutting would come out to be much higher. It clearly indicates that there is no likelihood of injury to the domestic industry in case of withdrawal of duties as the domestic industry is already commanding higher prices in the domestic market and the prices from the exporters from China are not going to come down in case of discontinuation of duties. It is also submitted that there is no analysis of the imports of subject goods into India under various duty-free schemes such as advance license in the disclosure statement as to how the same can be regarded as causing injury to the domestic industry.
119. In current sunset review there is no likelihood of either dumping or injury.
120. As there is negative injury margin for all exports from China, so there is no likelihood of injury to domestic industry.

121. The inventories of cooperative exporters alone cannot be used as a guiding factor for injury and likelihood analysis.
122. Indian market is not price attractive for cooperative exporters.
123. China Customs data is too remote so as to provide guidance about price attractiveness of Indian market. Analysis of price attractiveness should be done on the basis of data provided by cooperative exporters.
124. Volume of exports by domestic industry should be considered while doing causal link analysis.

N. Examination by the Authority

125. The post-disclosure comments made by the interested parties are mostly reiterations. However, the comments considered relevant by the Authority are addressed below:-

- a) As regards the request for disclosure of more information from the Authority such as normal value, NIP breakdown and actual data in injury analysis, the Authority notes that information disclosed is in full compliance with the Rules and Past practises of the Authority. All essential facts under Rule 16 of AD Rules have been disclosed. Furthermore, all non-confidential documents were kept in the public file for all interested parties for inspection.
- b) As regards the submission of the domestic industry that the non-injurious price determined is too low, the Authority notes that the NIP has been determined as per the Rules based on verified data and consistent practice of the Authority.
- c) As regards the stance of Government of India as expressed in documents such as Katoch Committee report, 145th Parliamentary report and Office Memorandum dated 18 April, 2018 issued by the Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Pharmaceuticals, the Authority notes that the present investigation was conducted as per Rules, facts of the case and past practices of the Authority.
- d) As Regards determination of NIP price it is clarified that NIP has been worked out based on the information/data submitted by domestic industry after due verification/reconciliation of fact and figures with audited accounts of the company and information submitted by the domestic industry during investigation. Net fixed assets is invariably adopted based on the book value of the assets excluding impact of revaluation and treatment given in this investigation is as per practice followed in all anti-dumping investigations.
- e) As regards the submission that there is no analysis of the imports of subject goods into India under various duty-free schemes such as advance license, the Authority notes that it has not concluded that there is injury to the Domestic industry on account of import of subject goods from China PR.
- f) As regards the contention regarding global production being bifurcated between China and India and the state of present domestic industry, the Authority notes that as per its injury analysis, the production of domestic industry of the subject goods is sufficient to cater to the Indian demand.

O. CONCLUSIONS

126. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in this final finding, the Authority concludes that:-

1. Evidence on record do not indicate that the dumped imports from China will lead to injury to Domestic Industry.
2. Import of the subject goods from China PR has remained at insignificant level throughout the injury period.
3. Domestic Industry failed to substantiate its claim in relation to likelihood of injury to the domestic industry if the current ADD ceases to exist.
4. The domestic injury has shown improvement in terms of all injury parameters and there is no injury to the Domestic industry. Furthermore, the production of subject goods by domestic industry is sufficient to cater to Indian demand.
5. The analysis of the price attractiveness by the Authority does not position India as price attractive for Chinese Exports so far as subject goods are concerned.
6. The ADD was in force since September' 2001 and the condition of domestic industry has improved. Therefore, the ADD has served its intended purpose.

P. Recommendation

127. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to domestic industry, exporters, importers, users and other interested parties to provide relevant information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, causal link and likelihood of dumping post cessation of ADD in force in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Act and Rules, the Authority holds that Domestic Industry failed to provide any satisfactory evidence that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry due to reasons and/or analysis given above. Therefore, the Authority does not recommend continuation of the anti-dumping duty on the imports of subject goods from China PR.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General